वर्ष 12 • अंक 285 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 17 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 6

आयातित खाद्य तेल के भंडार में गिरावट

अजय त्यागी ▶▶ पृष्ठ 3

कमोडिटी एक्सचेंजों को जिंसों में विकल्प कारोबार की अनुमति

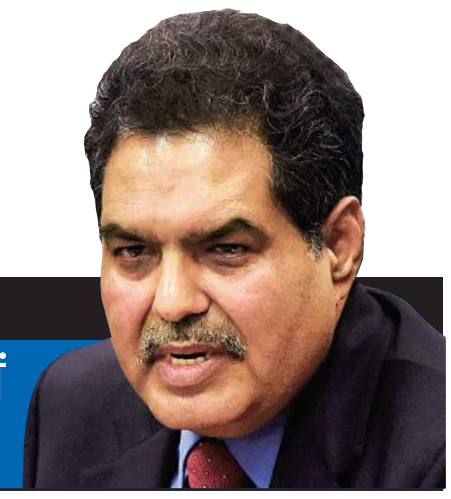

डॉलर रु. 70.90 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 79.20 ▲ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 39740 ▲ 86 रुपये | सेंसेक्स 41932.60 ▲ 59.80 | निफ्टी 12355.50 ▲ 12.20 | निफ्टी फ्यूचर्स 12374.30 ▲ 18.80 | ब्रेंट क्रूड 64.10 डॉलर ▼ 0.30 डॉलर

एक नज़र

अदाणी एंटरप्राइजेज के अधिकारियों पर मामला दर्ज

सीबीआई ने कोयले की आपूर्ति से जुड़े ठेके में कथित अनियमितता के मामले में अदाणी एंटरप्राइजेज और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के पूर्व चेयरमैन और पूर्व प्रबंध निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन को आयातित कोयले की आपूर्ति के ठेके से जुड़ा है। आरोप है कि उस समय एनसीसीएफ के चेयरमैन रहे विरेंदर सिंह और तत्कालीन प्रबंध निदेशक जीपी गुप्ता ने यह ठेका देने में अदाणी एंटरप्राइजेज का अनुचित तरीके से पक्ष लिया। एजेंसी ने सिंह और गुप्ता के साथ-साथ एनसीसीएफ के तत्कालीन वरिष्ठ सलाहकार एससी सिंघल और अदाणी एंटरप्राइजेज तथा अन्य अज्ञात अधिकारियों का नाम भी संदिग्ध के तौर पर दर्ज किया है। पृष्ठ 4

एयर एशिया के सीईओ और अन्य को समन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए एयर एशिया के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी किया है। ईडी ने कंपनी और इसके अधिकारियों के खिलाफ 2018 में धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। फर्नांडीस को पूछताछ के लिए 20 जनवरी को बुलाया गया है जबकि अन्य अधिकारियों को बाद में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने अपनी भारतीय इकाई एयर एशिया इंडिया को अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस दिलाने के लिए सरकारी नीतियों को गलत तरीकों से प्रभावित करने की कोशिश की। पृष्ठ 4

निवेश सलाहकारों, वितरकों की भूमिका होगी अलग

सेबी ने निवेश सलाहकार कंपनियों के लिए नए नियमों का मसौदा जारी कर 30 जनवरी तक सुझाव मांगे हैं। इसमें निवेश परामर्शदाताओं के परामर्श कामकाज और निवेश उत्पादों के वितरण को अलग करने का प्रस्ताव है। इसके पीछे सेबी का मकसद नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। परिचर्चा पत्र के अनुसार सेबी ने निवेश सलाहकारों को सुझाव दिया है कि उन्हें किसी भी निवेश सलाह के तहत लोगों को निश्चित रिटर्न मिलने का वादा नहीं करना चाहिए। निवेश परामर्श के लिए शुल्क लेने की प्रक्रिया तय करने और निवेश सलाहकारों के लिए नेटवर्थ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी है।

रिजर्व बैंक करेगा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि वह धन उपलब्धता और बाजार स्थिति को देखते हुए अगले गुरुवार को 10,000-10,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि मौजूदा समय में धन उपलब्धता और बाजार स्थिति की समीक्षा के बाद उसने 23 जनवरी 2020 को खुले बाजार परिचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का फैसला किया है।

धोनी के भविष्य पर संशय अनुबंध सूची से हुए बाहर

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को गुरुवार को बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से बाहर कर दिया गया। इससे उनके भविष्य को लेकर अटकलों का दौर फिर तेज हो गया है। धोनी ने पिछले साल विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद क्रिकेट नहीं खेला है।

त्यापार गोष्ठी

सरकारी अस्पतालों की बदहाली कैसे हो दूर?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें gosshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या एजीआर पर बढ़ेगी दूरसंचार फर्मों की मुश्किल

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या चीनी के लिए दोहरी मूल्य नीति होगी कारगर?	हां	62.50%
	नहीं	37.50%

एजीआर पर नहीं मिली राहत

सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की भारती और वोडाफोन आइडिया की समीक्षा याचिका

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 16 जनवरी

बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर शीर्ष अदालत के फैसले पर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा दायर समीक्षा याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया। इससे पहले अदालत ने 23 जनवरी तक दूरसंचार कंपनियों को 1.47 लाख करोड़ रुपये का बकाया एजीआर चुकाने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति एमआर शाह के पीठ ने कहा समीक्षा याचिका को खारित करते हुए कहा कि यह सुनवाई के लिए पात्र नहीं है। एजीआर सेवा प्रदाताओं का राजस्व होता है, जिसमें गैर-मुख्य दूरसंचार परिचालनों जैसे किराया, लाभांश और ब्याज आय शामिल होते हैं। यह केवल दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त आय नहीं है। अदालत के आदेश से निराश भारती एयरटेल ने कहा कि वह सुधारात्मक याचिका दायर करने पर विचार कर रही है, जो अदालत में शिकायत निपटान का अंतिम उपाय है। भारती एयरटेल ने कहा, 'उद्योग भारी वित्तीय दबाव में है और अदालत के फैसले से पूरे क्षेत्र की व्यवहार्यता पर और संशय खड़ा होगा। उद्योग को नेटवर्क के विस्तार, स्पेक्ट्रम खरीदने और 5जी जैसी नई तकनीकी पर निरंतर निवेश करने की जरूरत है।'

बढ़ेगी मुश्किल

- दूरसंचार कंपनियों को बकाया एजीआर मद में 1.47 लाख करोड़ रुपये का करना है भुगतान
- भारती एयरटेल सुधारात्मक याचिका दायर करने पर कर रही विचार

24 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की एजीआर की परिभाषा को सही ठहराया था। इसे लेकर दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।

सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने एजीआर की गणना के लिए सरकार की परिभाषा को चुनौती देते हुए 2005 में पहला मामला दायर किया था। उसकी दलील थी कि सरकार एजीआर में जिन घटकों को शामिल करने की कोशिश कर रही है वे टेलीग्राफ ऐक्ट और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के अनुरूप नहीं हैं।

दूरसंचार उद्योग दूरसंचार विभाग द्वारा मांगी गई राशि के 85 फीसदी हिस्से का भुगतान कर चुका है लेकिन शेष 15 फीसदी राशि पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसकी वजह यह है कि दूरसंचार कंपनियों को दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील पंचाट, उच्च न्यायालयों और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय से भी अनुकूल फैसला मिल रहा है। दूरसंचार कंपनियों पर सरकार का 92,641 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें 23,189 करोड़ रुपये विवादित वास्तविक मांग, 41,650 करोड़ रुपये ब्याज, 10,923 करोड़ रुपये जुर्माना और 16,878 करोड़ रुपये जुर्माने पर ब्याज शामिल है। अगर इसमें लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क को भी शामिल कर लिया जाए तो यह राशि 1.47 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगी। एसयूसी की गणना एजीआर पर की गई है। दिसंबर में वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अगर उनकी कंपनी को सरकार की तरफ से राहत नहीं मिली तो वह बंद हो जाएगी। कंपनी को सरकार को 40 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

वोडाफोन आइडिया को एजीआर के बकाये के भुगतान का प्रावधान करने के बाद सितंबर तिमाही में 50,922 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था जो भारत के कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घाटा है। एयरटेल को भी सितंबर में समाप्त तिमाही में 23,044 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। उसने एजीआर बकाये के लिए 28,450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगी और कर रियायत!

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 16 जनवरी

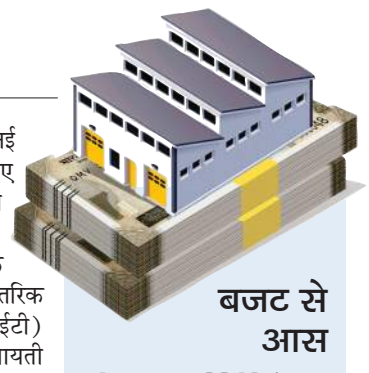

बजट से आस

- 1 अक्टूबर, 2019 से कुछ महीने पहले इकाई लगाने वाली कंपनियों को भी कम कॉरपोरेट कर के दायरे में लाने की मांग
- वाणिज्य विभाग ने की विनिर्माण क्षेत्र के लिए रियायती कर की दर दो साल तक बढ़ाने की मांग

सरकार इस बार के बजट में नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कॉरपोरेट कर की दर में रियायत को दो साल तक और बढ़ा सकती है। इन्वेस्ट इंडिया के अलावा निवेश संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) नई इकाइयों के लिए रियायती कॉरपोरेट कर की दर को आगे बढ़ाने और इसे पिछले कुछ महीनों से लागू करने की वकालत कर रहा है ताकि 1 अक्टूबर की समयसीमा चूकने वालों को भी इसका लाभ मिल सके।

वित्त मंत्रालय को दिए प्रस्ताव में वाणिज्य विभाग ने 15 फीसदी के कम कॉरपोरेट कर को दो साल तक बढ़ाने की मांग की है। इससे कंपनियों को उत्पादन शुरू करने के लिए 31 मार्च, 2025 तक का वक्त मिलेगा जबकि अभी इसकी समयसीमा 2023 है। यह कदम कंपनियों को लंबा समय देने के साथ ही भारत को 2024-25 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के अनुरूप भी है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कुछ क्षेत्रों में उत्पादन शुरू करने में लंबा वक्त लगता है और उन्हें पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर काम करना होता है। कर रियायत की सुविधा 2025 तक करने से इन क्षेत्रों को काफी वक्त मिल सकेगा।' अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 सितंबर, 2019 को नई विनिर्माण इकाइयों को कॉरपोरेट कर में छूट देने की घोषणा की थी। हालांकि इकाई की स्थापना का काम 1 अक्टूबर, 2019 से शुरू कर 31 मार्च, 2023 तक उत्पादन शुरू करने की शर्त रखी गई थी। ऐसी इकाइयों से 15 फीसदी कर दर से कॉरपोरेट कर लेने की घोषणा की गई थी। इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से भी राहत दी गई थी। किसी तरह की रियायत नहीं लेने वाली मौजूदा कंपनियों के लिए भी कर की दर घटाकर 25 फीसदी की गई थी।

इन्वेस्ट इंडिया ने अप्रैल के बाद इकाई लगाने वाली कंपनियों की सूची तैयार कर रही है, जो कुछ दिन या महीनों से रियायती दर का लाभ उठाने से चूक गईं हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'विभिन्न क्षेत्रों में कई विदेशी कंपनियों ने कम कर की दर का लाभ नहीं उठा पाने को लेकर निराशा जाहिर की है क्योंकि उन्होंने सितंबर या अगस्त में अपनी इकाइयां लगाई थीं।'

(शेष पृष्ठ 4 पर)

बजट में मिले दिल्ली को पर्याप्त धन

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 16 जनवरी

- आचार संहिता लागू होने के बावजूद केजरीवाल ने केंद्र से की मांग
- प्रदूषण रोकने और परिवहन मजबूत करने के लिए मिले धन
- दिल्ली के नगर निगमों के लिए भी बजट में फंड का हो प्रावधान

आम तौर पर आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दल बजट में संबंधित चुनावी राज्य के लिए लुभावनी घोषणाएं न करने की मांग करते हैं लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए घोषणाओं को रोकने के बजाय नई घोषणाएं करने और इनके लिए पर्याप्त कोष मुहैया कराने की मांग की है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आचार संहिता लागू होने से कोई भी सरकार नई नीति की घोषणा नहीं कर सकती है क्योंकि मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को पेश होगा, उससे भी मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। केजरीवाल ने कहा, ' मुझ पर पार्टी और बाहर से दबाव आया कि चुनाव आयोग को लिखें कि केंद्र सरकार को 1 फरवरी को बजट पेश करने से रोका जाए। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए और राजनीति को विकास से अलग रखना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि बजट 1 फरवरी को ही पेश हो और इस बजट में दिल्ली के विकास के लिए खूब घोषणाएं की जाएं। आम बजट में दिल्ली के अंदर प्रदूषण को दूर करने के लिए उचित फंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।' पंजाब, हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली से निजात दिलाने के लिए भी इन राज्यों के लिए फंड का प्रावधान बजट में हो। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि दिल्ली के परिवहन को विश्व स्तरीय बनाने, यमुना को साफ करने, घर घर तक पानी, सीवर, मेट्रो के विस्तार, दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए आम बजट में दिल्ली सरकार को धन मुहैया कराने का प्रावधान हो।' दिल्ली की नगर निगम में पैसे की किल्लत है। इसलिए बजट में दिल्ली की नगर निगमों को भी उचित आवंटन मिले।

इससे पहले दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बजट पूर्व मांग में दिल्ली के लिए बजट में 13,000 करोड़ रुपये देने की मांग की थी। साथ ही बजट में दिल्ली के लिए केंद्रीय करों, सामान्य सहायता, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सा बढ़ाने के साथ ही नगर निगम के लिए 1,250 करोड़ रुपये मांगे थे।

दूरसंचार फर्में बिना दावे वाला धन ग्राहक शिक्षा कोष में जमा कराएं : दूरसंचार कंपनियों को ग्राहकों की आरक्षित राशि और अतिरिक्त शुल्क जैसे बिना दावे वाले धन को एक निश्चित समयसीमा के बाद दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षा कोष में जमा कराना होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने गुरुवार को यह स्पष्टीकरण दिया। *भाषा*

वॉकहार्ट की एंटीबायोटिक मंजूर

सोहिनी दास
मुंबई, 16 जनवरी

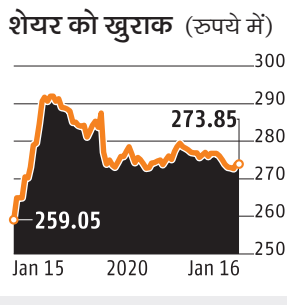

वॉकहार्ट की उपलब्धि...

- यह मंजूरी पाने वाली देश की पहली कंपनी
- 15 साल से इस श्रेणी में नहीं आई है कोई दवा
- त्वचा की बीमारियों के इलाज में आती है काम
- उभरते बाजारों और चीन में भी उतारने की तैयारी

मुंबई की दवा कंपनी वॉकहार्ट को दो नई नोवल एंटीबायोटिक दवाओं के लिए नियामक की मंजूरी मिल गई है। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय कंपनी को नई एंटीबायोटिक उतारने की अनुमति मिली है। वॉकहार्ट की अगले कुछ महीनों में इन दवाओं को बाजार में उतारने की योजना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में नई एंटीबायोटिक उतारी हैं लेकिन पिछले 15 साल में भारत में इस श्रेणी में कोई नई एंटीबायोटिक नहीं आई है।

कंपनी की योजना इन दवाओं को जल्दी ही उभरते बाजारों और चीन में उतारने की है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले 18 से 24 महीने में इन दवाओं का ब्रांड 100 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच जाएगा। नई दवा ऐसे सुपरबग के खिलाफ कारगर होगी जिन पर दूसरी दवाएं नाकाम हो रही हैं। इस घोषणा के बाद कंपनी के शेयर की कीमतों में भारी तेजी आई। बीएसई पर यह 5.71 फीसदी चढ़कर 273.85 रुपये पर बंद हुआ।

भारतीय दवा महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने दो नई एंटीबायोटिक एमरॉक (इंजेक्टेबल) और एमरॉक ओ (ओरल) को मंजूरी दी है। इनका इस्तेमाल त्वचा की बीमारियों में किया जाता है। यह मंजूरी देशभर में 40 केंद्रों में 500 मरीजों पर तीन चरणों में किए गए चिकित्सीय परीक्षणों पर आधारित है।

अभी दुनियाभर में एंटीमाइक्रोबायल रेजिसटेंस (एएमआर) जनस्वास्थ्य को लेकर चिंता का प्रमुख कारण है। भारत में 2050 तक एमएमआर की वजह से 20 लाख लोगों के जान गंवाने की आशंका है। ऐसे रोगाणुओं के संक्रमण से मृत्यु दर बढ़ सकती है और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। खासकर भारत में इस समस्या का खतरा अधिक है। वॉकहार्ट के प्रबंध निदेशक मुर्तजा खोराकीवाला ने कहा कि इस श्रेणी में भारी मांग है। उन्होंने कहा, 'वॉकहार्ट देश की पहली दवा कंपन बन गई है जिसे भारत में खोजी गई, विकसित की गई और बनी नोवल एंटीबायोटिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है।'

वॉकहार्ट की दो नई दवाएं एमरॉक (इंजेक्टेबल) और एमरॉक ओ (ओरल) अस्पताल में दी जाने वाली एंटीबायोटिक है। इसे अस्पतालों में गंभीर संक्रमण के इलाज के लिए दिया जाएगा। देश के 16000 करोड़ रुपये के एंटीबायोटिक बाजार में 30 से 40 फीसदी इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक हैं। देश के कुल दवा बाजार में एंटीबायोटिक का हिस्सा 12 फीसदी है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

ग्रेन्युल्स इंडिया

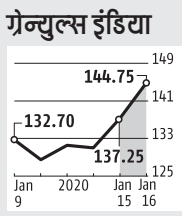

शेयर पुनर्खरीद प्रस्ताव पर विचार के लिए 21 जनवरी को होगी बोर्ड बैठक

₹ 137.25 पिछला बंद भाव
₹ 144.75 आज का बंद भाव
▲ 5.46 %

स्टरलाइट टेक्नोलॉजिज

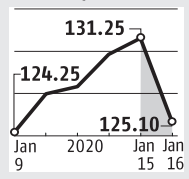

तीसरी तिमाही में एबिटा सालाना आधार पर 18.7 फीसदी घटा

₹ 131.25 पिछला बंद भाव
₹ 125.10 आज का बंद भाव
▼ 4.69 %

नेस्ले इंडिया

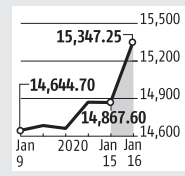

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर

₹ 14,867.60 पिछला बंद भाव
₹ 15,347.25 आज का बंद भाव
▲ 3.23 %

वॉकहार्ट

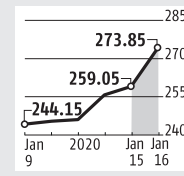

विशेष एंटीबायोटिक्स के लिए मंजूरी पाने वाली पहली भारतीय कंपनी

₹ 259.05 पिछला बंद भाव
₹ 273.85 आज का बंद भाव
▲ 5.71 %

टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स

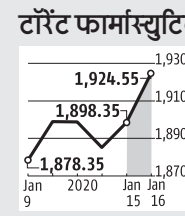

रकम जुटाने की योजना पर विचार के लिए 27 जनवरी को बोर्ड बैठक

₹ 1,898.35 पिछला बंद भाव
₹ 1,924.55 आज का बंद भाव
▲ 1.38 %

संक्षेप में

एचडीएफसी एर्गो हेल्थ का होगा विलय

एचडीएफसी एर्गो हेल्थ का एचडीएफसी एर्गो में विलय किया जाएगा जिसे शेयर अदला-बदली के जरिये अंजाम दिया जाएगा। एचडीएफसी एर्गो हेल्थ को पहले अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता था। एचडीएफसी एर्गो और एचडीएफसी एर्गो हेल्थ के निदेशक मंडल की 15 जनवरी को हुई बैठक में दोनों इकाइयों के विलय को मंजूरी दी गई। एचडीएफसी लिमिटेड ही साधारण बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो की प्रवर्तक है। विलय से एचडीएफसी एर्गो भंग हो जाएगी और इसे बंद करने की जरूरत नहीं होगी। *भाषा*

जेएसडब्ल्यू की फॉर्मा का परिचालन साल भर में बंद

जेएसडब्ल्यू समूह की कंपनी फॉर्मा ने शुरुआत के एक साल के भीतर ही अपना परिचालन बंद कर दिया है। एक सूत्र ने इसकी जानकारी दी। जेएसडब्ल्यू लिविंग ने पिछले साल अप्रैल में फॉर्मा को पेश किया था। फॉर्मा इस्पात फर्नीचर क्षेत्र की कंपनी है। घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने कहा, कारोबार व्यवहार्य नहीं रह जाने से फॉर्मा ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। इसके मुख्य कार्याधिकारी वेदराज त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने इसके बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। *भाषा*

स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने ओडिशा स्पंज की हिस्सेदारी बेची

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने ओडिशा स्पंज आयरन ऐंड स्टील की अपनी पूरी 18.46 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी है। ओडिशा स्पंज आयरन ने गुरुवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि यह बिक्री बुधवार को हुई। ओडिशा स्पंज आयरन ऐंड स्टील कंपनी ओडिशा सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऐंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा और टॉरस्टील रिसर्च फाउंडेशन इन इंडिया का साझा उपक्रम है। *भाषा*

3,900 अरब डॉलर के आईटी खर्च का अनुमान

सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पर वैश्विक खर्च वर्ष 2020 में एक साल पहले की तुलना में 3.4 फीसदी बढ़कर 3,900 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। शोध एवं परामर्श क्षेत्र की वैश्विक कंपनी गार्टनर ने यह अनुमान जताते हुए कहा है कि वर्ष 2021 में वैश्विक कंपनियों का आईटी खर्च बढ़कर चार हजार अरब डॉलर के पार भी जा सकता है। *भाषा*

सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की दूरसंचार कंपनियों की एजीआर समीक्षा याचिका

एयरटेल व जियो रहेगी फायदे में, वोडा-आइडिया पर संकट

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 16 जनवरी

यह समझना मुश्किल नहीं है कि आज के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सबसे ज्यादा लाभ किसे मिलेगा, जिसने एजीआर के बकाए के भुगतान पर अपने पहले के फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। पहले स्थान पर रिलायंस जियो होगी जबकि दूसरे स्थान पर भारती एयरटेल। स्पष्ट तौर पर वोडाफोन-आइडिया के लिए चिंता की बात होगी और सवाल यह है कि क्या कंपनी अपना परिचालन बंद करेगी या फिर उसे चालू रखेगी।

इसकी वजह सामान्य है : जियो पर एजीआर का असर नगण्य है क्योंकि उसे सिर्फ 60 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। ऐसे में इस कंपनी पर वित्तीय असर नगण्य होगा, लेकिन उसके लिए 50 करोड़ ग्राहक हासिल करने का लक्ष्य तय करना आसान होगा। अभी जियो हर महीने 80-90 लाख ग्राहक जोड़ रही है, ऐसे में लक्षित आंकड़े तक पहुंचने में उसे 16-18 महीने लगेंगे। लेकिन कमजोर वोडाफोन आइडिया अगर परिचालन बंद करने का फैसला लेती है तो इस कंपनी के 31.1 करोड़ ग्राहक बाजार में होंगे, जिसका एक हिस्सा निश्चित तौर पर जियो हासिल करेगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2जी-3जी ग्राहक, 4जी की ओर जाएंगे। 4जी फीचर फोन के जरिए जियो के पास आकर्षक पेशकश है, जिसकी कीमत 699 रुपये है। इसके तहत 2जी फोन को 4जी फोन में तब्दील किया जाएगा और जेब पर भी भार नहीं पड़ेगा।

भारती के लिए इस पैसले का मतलब यह होगा कि कंपनी को एजीआर का बकाया चुकाने के लिए क्यूआईपी व एफसीसीबी के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल करना होगा, जो 48,000 करोड़ रुपये है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि सरकार कार्यकारी आदेश के जरिये इस भुगतान को टुकड़ों में करने की योजना पेश कर सकती है, जो दबाव घटाएगा। लेकिन सकारात्मक चीज यह है कि कंपनी का शुद्ध कर्ज-एबिटा अनुपात 3.3 फीसदी के नियंत्रित स्तर पर है।

कमजोर वोडाफोन आइडिया अगर परिचालन बंद करती है को भारती को इसका फायदा मिल सकता है। जियो को इसका उतना फायदा नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए वोडाफोन आइडिया के 7.3 फीसदी ग्राहक पोस्टपेड हैं और विश्लेषकों का कहना है कि राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 20 फीसदी से ज्यादा है क्योंकि उनका एआरपीयू ज्यादा है। इसके उलट एयरटेल के 5.6 फीसदी ग्राहक पोस्टपेड हैं और कंपनी ने इस क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी बनने की रणनीति बनाई है। अगर वोडाफोन आइडिया दुकान बंद करती है या फिर कमजोर होती है तो उच्च एआरपीयू वाले ज्यादातर ग्राहक एयरटेल की ओर जाएंगे। जियो के पास पोस्टपेड में बहुत ज्यादा नहीं है और उसने प्रीपेड बाजार में ही आक्रामक रहना पसंद किया है। जियो के पास इसमें एकमात्र पेशकश 199 रुपये की है, जो उसके ग्राहक आधार का महज एक फीसदी है।

दूसरा, वोडाफोन आइडिया के ज्यादातर ग्राहक 2जी फोन का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ कुछ ही डेटा का उपभोग करते हैं। ताजा आंकड़ों के आधार पर कंपनी के पास 20 करोड़ 2जी ग्राहक हैं और इनमें से 3.8 करोड़ डेटा इस्तेमाल करते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि उनमें से कई 2जी नेटवर्क में रहना चाहेंगे और एयरटेल उन्हें मौका उपलबब्ध करा सकता है। दूसरी ओर जियो के पास 4जी नेटवर्क है। साथ ही टैरिफ भी 15 से 40 फीसदी तक बढ़ा है, जो 2जी ग्राहकों को दूसरी तरफ जाने के पहले कई बार सोचने को बाध्य कर रहा है। जियो के आने के बाद भी भारती अपनी राजस्व बाजार हिस्सेदारी 30 फीसदी पर बनाए रखने में कामयाब रही है। सुनील मित्तल ने गोल्डमैन सैक्स से मुलाकात में कहा है कि वह बाजार हिस्सेदारी में बढ़त का 50 फीसदी हासिल करने में सक्षम है।

वोडाफोन के लिए सबसे बड़ी चुनौती 54,000 करोड़ रुपये के भुगतान की है और वह पहले से ही कर्ज में डूबी है। वोडाफोन व कुमारमंगलम बिड़ला सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो वे परिचालन बंद कर देंगे।

अच्छी खबर यह है कि सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए दो साल की मोहलत दे दी है, जो कंपनियों के हाथ में अभी करीब 25,000 करोड़ रुपये रखता है। भविष्य की उनकी रणनीति स्पष्ट तौर पर इस पर निर्भर करेगी कि सरकार टुकड़ों में भुगतान की क्या पेशकश करती है ताकि असर कम हो। सीओएआई पहले ही 10 साल की मोहलत की मांग कर चुका है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निहितार्थ

- जियो पर एजीआर का असर नगण्य है क्योंकि उसे सिर्फ 60 करोड़ रुपये चुकाने होंगे
- भारती के लिए इस फैसले का मतलब यह होगा कि कंपनी को एजीआर का बकाया चुकाने के लिए क्यूआईपी व एफसीसीबी के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल करना होगा, जो 48,000 करोड़ रुपये है
- कमजोर वोडाफोन आइडिया अगर परिचालन बंद करती है, तो भारती को इसका फायदा मिल सकता है। जियो को इसका उतना फायदा नहीं मिलेगा
- अगर वोडाफोन आइडिया दुकान बंद करती है या फिर कमजोर होती है तो उच्च एआरपीयू वाले ज्यादातर ग्राहक एयरटेल की ओर जाएंगे
- जियो के पास पोस्टपेड में बहुत ज्यादा नहीं है, उसने प्रीपेड बाजार में ही आक्रामक रहना पसंद किया है

500 से 800 सीसी मोटरसाइकल की बिक्री 4 गुना बढ़ी

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 16 जनवरी

300 से 500 सीसी इंजन क्षमता समेत पूरे दोपहिया क्षेत्र की बिक्री वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में घटी, लेकिन 500 से 800 सीसी इंजन क्षमता वाले वाहनों की बिक्री करीब चार गुना बढ़ गई। बढ़त की इस रफ्तार की अगुआई रॉयल एनफील्ड की दो मोटरसाइकल ने की।

वाहन निर्माताओं के संगठन सायम के आंकड़ों के मुताबिक, 500-800 सीसी इंजन क्षमता वाले वाहनों की बिक्री अप्रैल-दिसंबर 2019 में बढ़कर 18,241 पर पहुंच गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 3,595 रही थी। इस श्रेणी में बाजार की अग्रणी कंपनी ने इसका कारण बड़ी बाइक की ओर जाने का ग्राहकों का फैसला था।

- दोपहिया की बिक्री 15.80 फीसदी घटने के बावजूद इस तरह की मोटरसाइकल ने पकड़ी रफ्तार

500-800 सीसी इंजन क्षमता वाले वाहनों में पिछली कुछ तिमाहियों में तेज बढ़ोतरी हुई है और रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 ने इस बढ़त में अहम भूमिका निभाई, यानी उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही।

सायम के आंकड़े बताते हैं कि 500 सीसी से ऊपर लेकिन 800 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली श्रेणी के तौर पर वर्गीकृत इस क्षेत्र में रॉयल एनफील्ड की हिस्सेदारी वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में करीब 87.27 फीसदी (15,920 वाहन) रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 25 फीसदी (954 वाहन) रही थी। यह ऐसे समय में हुआ है जब दोपहिया की बिक्री अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान 15.80 फीसदी घटकर 1,39,14,974 वाहन रह घई, जो एक साल पहले 1,65,26,785 वाहन रही थी।

इस श्रेणी में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एच-डी मोटर कंपनी इंडिया (हार्ली डेविडसन इंडिया) ने बिक्री में मामूली गिरावट दर्ज की और उसकी बिक्री 1,441 वाहन से घटकर 1,406 रह गई। अन्य कंपनियों में इंडिया कावासाकी मोटर्स (468 वाहन), ट्रायम्फ (145), सुजूकी (131), होंडा (100) और बजाज ऑटो (64) शामिल हैं।

रॉयल एनफील्ड के प्रवक्ता ने कहा, 650 सीसी वाली दोनों मोटरसाइकल को भारत व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। प्रवक्ता ने कहा, रॉयल एनफील्ड ने मध्यम आकार वाले क्षेत्र के ऊपरी हिस्से को भरने का काम किया क्योंकि यह क्षेत्र मोटे तौर पर खाली रहा है और भारत में इस कीमत आदि पर शायद ही कोई मोटरसाइकल है। 650 सीसी वाली दोनों मोटरसाइकलों ने इस श्रेणी में ब्रांड का विस्तार करने में मदद की। 650 सीसी वाली दोनों मोटरसाइकल के ज्यादातर खरीदार हालांकि रॉयल एनफील्ड के मौजूदा ग्राहक ही हैं। हालांकि कुछ नए ग्राहक भी इस ब्रांड से पहली बार जुड़े।

वॉकहार्ट की एंटीबायोटिक मंजूर

पृष्ठ 1 का शेष

वॉकहार्ट की योजना इन दवाओं को उभरते बाजारों में उतारने की है। साथ ही वह साझेदारी के जरिये चीन के बाजार में भी प्रवेश करना चाहती है। बिक्री के लिहाज से चीन दुनिया में एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा बाजार है। वॉकहार्ट के संस्थापक और चेयरमैन हबील खोराकीवाला ने कहा कि डॉलर के लिहाज से चीन का एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल बाजार अमेरिका से दोगुना बड़ा है।

हर्शी ने भारत में अपने वैश्विक ब्रांड पेश किए

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 16 जनवरी

भारत में आठ साल से परिचालन कर रही चॉकलेट निर्माता हर्शी ने यहां अपने वैश्विक पोर्टफोलियो को पेश करने का निर्णय लिया है। कंपनी पूरे भारत में अपने हर्शी चॉकलेट और कन्फेक्शनरीज के लोकप्रिय किसेज ब्रांड को पेश कर रही है जिससे बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में उसके पोर्टफोलियो को मजबूती मिल सकती है।

कंपनी ने यह कोशिश ऐसे समय में की है जब उसे यहां मुनाफे की स्थिति में आने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हर्शी इंडिया को 2014-15 से नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि वह पिछले दो वर्षों से नुकसान में कमी लाने में सफल रही है। जहां उसने 2014-15 में 365 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान दर्ज किया था, वहीं 2018-19 में यह 109 करोड़ रुपये रह गया।

हर्शी इंडिया के प्रबंध निदेशक हरजीत भल्ला के अनुसार, परिचालन के शुरुआती वर्षों के दौरान कंपनी की ब्रांड निर्माण पहलों और चैनल विकास गतिविधियों का उसके राजस्व पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा, 'हम भारत में अभी भी नई कंपनी हैं और पिछले दो वर्षों में हमने जॉली रैंचर, ब्रुकसाइड और किसेज जैसे अपने वैश्विक उत्पादों को पेश करने के लिए बड़ा निवेश किया।'

यहां तीन वैरिएंट में पेश किए गए हर्शी बार्स अमेरिकी कंपनी के पहले उत्पाद हैं, जिन्हें 110 साल पहले अमेरिकी चॉकलेट बाजार में प्रवेश के दौरान पेश किया गया था।

देश में महंगे से लेकर औसत चॉकलेट और कन्फेक्शनरी उत्पादों की कीमतों के लिहाज से हर्शी के उत्पाद मुख्य रूप से शहरी उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर पेश किए गए हैं। कंपनी अब नए ब्रांड 70 शहरों में सिर्फ लार्ज-फॉर्मेट किराना स्टोरों, अत्याधुनिक कारोबार और ई-कॉमर्स पोर्टलों पर उपलब्ध कराना चाहती है।

घाटा कम करने पर जोर देगी एयर इंडिया

अनीश फडणीस और अरिंदम मजूमदार
मुंबई/नई दिल्ली, 16 जनवरी

एयर इंडिया को टिकट वितरण और विमानों के बेहतर इस्तेमाल तथा नई उड़ानों की पेशकश के जरिये राजस्व बढ़ाकर अपनी बचत दोगुनी किए जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय एयरलाइन को भारी कर्ज की वजह से वित्तीय संघर्ष से जूझना पड़ रहा है। राजस्व में वृद्धि के बावजूद उसे हर महीने लगभग 200 करोड़ रुपये की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतान में विलंब की स्थिति गहरा गई है। एयरलाइन में दिसंबर महीने का वेतन गुरुवार

को दिया गया था। हालांकि एयरलाइन के प्रबंधन को इस साल परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार आने की उम्मीद दिख रही है। बिक्री और वितरण अनुबंधों पर पुन: बातचीत से एयरलाइन को लागत बचाने में मदद मिल रही है। अक्टूबर 2018 में एयर इंडिया ने देश में अपने विशेष टिकट वितरण भागीदार केतौर पर वैश्विक वितरण सेवा (जीडीएस) ट्रैवलपोर्ट को चुना था। तब तक एयरलाइन भारत में टिकट वितरण के लिए तीन कंपनियों एमाडियस, सैब्रे और ट्रैवलपोर्ट पर निर्भर थी। सैब्रे के साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद घरेलू टिकटिंग के लिए विशेष समझौते जनवरी से लागू हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बिक्री के लिए एयरलाइन ने एमाडियस और ट्रैवलपोर्ट के साथ भागीदारी की है और उसने इन कंपनियों से काफी कम दरें हासिल की हैं। एयरलाइन की वाणिज्यिक निदेशक मीनाक्षी मलिक ने कहा, 'हमने जीडीएस के बेहतर इस्तेमाल के जरिये 2020 में 520 करोड़ रुपये की बचत का लक्ष्य रखा है।' 2019 में एयरलाइन ने जीडीएस लागत पर 227 करोड़ रुपये की बचत की थी।

बीएस बातचीत

भारत-केंद्रित पूंजी को तेजी के संकेत का इंतजार

स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स के प्रबंध निदेशक एवं निवेश प्रमुख (भारत) **सतीश बेतादपुर** ने **ऐश्ली कुटिन्हो** के साथ साक्षात्कार में कहा कि मूल्यांकन के नजरिये से उभरते बाजार 2020 में आकर्षक दिख रहे हैं। सीएफए सोसायटी इंडिया के 10वें इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय इक्विटी का ध्रुवीकरण निवेश परिवेश में बदलाव तक बरकरार रहेगा। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश:

क्या आप मानते हैं कि उभरते बाजार में निवेश 2020 में आकर्षक थीम बन सकता है?

उभरते बाजार आकर्षक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं और आय वृद्धि में तेजी आने की संभावना है। मजबूत डॉलर से भी मदद मिल सकती है। उभरते बाजारों ने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और इसकी मुख्य वजह चीन है, जो इस सूचकांक का बड़ा हिस्सा है। देश में अत्यधिक क्षमता वृद्धि दर्ज की है और व्यापार युद्ध से मदद नहीं मिली। यह उन बड़े बाजारों में से एक है जहां पिछले दशक में कमजोर रिटर्न दर्ज किया गया। कुल मिलाकर, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, अमेरिका में चुनाव, ब्रेक्सिट, और पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर निवेशकों की नजर बनी हुई है। हालांकि अमेरिका-ईरान गतिरोध अस्थायी दिख रहा है। दोनों पक्ष पीछे हटे हैं और हमारा मानना है कि तनाव अब ज्यादा नहीं बढ़ सकता है।

ईएम बाजारों में भारत की स्थिति कैसी है?

निवेशक सामान्य तौर पर उभरते बाजारों पर सकारात्मक रहे हैं और भारत उस पूंजी का बड़ा हिस्सा आकर्षित करेगा जो ईएम सूचकांकों में खरीदारी से जुड़ी हुई है। तिमाही दर तिमाही एनएवी-केंद्रित पूंजी प्रबंधकों से निवेश के लिहाज से तेजी के स्पष्ट संकेत का इंतजार किया जा सकता है। मौजूदा समय में, हमें किसी तेजी का स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहा है। दीर्घावधि निवेशकों के लिए अवसर मौजूद हैं और यही वजह है कि निजी लेनदेन में तेजी आ रही है और निजी इक्विटी कारोबारी कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी ले रहे हैं।

मौजूदा आर्थिक मंदी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

हमें उम्मीद है कि भारत इस साल अच्छा प्रदर्शन करेगा और बैंकिंग संकट की तीव्रता घटेगी। दिवालिया कानून रकम वापसी के लिए एक अच्छी पहल है। चूंकि बड़े एनपीए से रकम फिर से बैंकिंग व्यवस्था में आती है जिससे ऋण वृद्धि की रफ्तार तेज हो सकती है। फिलहाल, ऋण वृद्धि की संभावना नहीं देख रहे हैं, क्योंकि किसी को भी व्यवसाय के लिए उधारी का भरोसा नहीं है।

आगामी बजट से सरकार से क्या उम्मीदें हैं?

कॉरपोरेट कर दर में कटौती एक अच्छी पहल थी। अब हम आय कर में कुछ कटौती के बारे में सुन रहे हैं। यह पहले ही हो जाना चाहिए था। उम्मीद है कि इस बार ऐसा होगा।

कमोडिटी एक्सचेंजों को जिंसों में विकल्प कारोबार की अनुमति

राजेश भयानी
मुंबई, 16 जनवरी

बाजार नियामक सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स में बड़े सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए स्टॉक एक्सचेंजों को कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में 'ऑप्शन ऑन गुड्स' (जिंसों में विकल्प) शुरू करने की अनुमति दी है। यह 'कमोडिटी फ्यूचर्स पर ऑप्शन' से अलग है। माल पर ऑप्शन के मानक फ्यूचर्स पर ऑप्शन की तुलना में आसान हैं।

मौजूदा समय में कमोडिटी ऑप्शन की अनुमति उस जिंस के फ्यूचर्स के आधार पर हासिल है। इसका मतलब है कि ऑप्शन के निपटान पर, यह फ्यूचर्स में तब्दील हो जाता है या निपटान पर बिक्री नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक ऑप्शन कारोबार फ्यूचर्स में समाप्त होता है।

सेबी ने एक्सचेंजों को समान जिंसों के साथ गुड्स पर ऑप्शन और फ्यूचर्स पर ऑप्शन की भी अनुमति दी है, हालांकि दोनों के लिए पोजीशन सीमा को एक साथ जोड़ा जाएगा और गुड्स पर ऑप्शन के लिए अनुबंध शर्तें कमोडिटी फ्यूचर्स के समान रहेंगी।

विकल्प कारोबार में सबसे बड़ी बाजार भागीदारी वाले एमसीएक्स के प्रबंध निदेशक पी एस रेड्डी ने कहा, 'जिंस डेरिवेटिव बाजार के विकास की दिशा में यह एक बड़ा सुधार है। इससे एक्सचेंजों को उन उत्पादों की पेशकश के लिए स्वायत्तता मिली है जो हितधारकों के एक बड़े वर्ग की जरूरत पूरी करते हैं और इससे बाजार दक्षता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।'

सेबी ने कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस आदि जैसी जिंसों को शामिल करने के लिए जिंसों पर ऑप्शन के साथ साथ गुड्स पर ऑप्शन की अनुमति दी है।

एक्सचेंजों को 'ऑप्शन इन गुड्स' (लॉन्ग और शॉर्ट दोनों) में प्रमुख 10 सबसे बड़े कारोबारियों/कारोबारियों के समूह के ओपन इंटरेस्ट जैसे जरूरी खुलासे करने होंगे। सिर्फ वही माल इन ऑप्शन के लिए योग्य होगा, जिस पर एक्सचेंज या तो वायदा अनुबंध पहले से कर रहा हो, या वायदा अनुबंध शुरू करने की तैयारी कर रहा हो।

सबसे बड़े कृषि केंद्रित कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के बिजनेस हेड कपिल देव ने कहा, 'अब हम गेहूं, मक्का और मसालों में ऑप्शन की संभावना तलाशेंगे और इसके लिए हम वायदा अनुबंध की पेशकश कर रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन हेजिंग और/या किसानों के उत्पादों की डिलिवरी के लिए वायदा का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं। अब ऑप्शन में ज्यादा जिंसों को शामिल किया जा सकेगा। हालांकि हम उन ऑप्शन अनुबंधों में 'ऑप्शन ऑन गुड्स' शुरू करने की संभावना नहीं तलाश रहे हैं जिनमें हम पहले से ही पेशकश कर रहे हैं।'

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के सहायक निदेशक किशोर नार्ने ने कहा, 'कमोडिटी एक्सचेंजों को फ्यूचर्स में ऑप्शन शुरू करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का न्यूतम दैनिक औसत कारोबार जरूरी है। इसलिए, बीएसई और एनएसई जैसे एक्सचेंज ऑप्शन शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दैनिक औसत कारोबार इस सीमा से नीचे बना हुआ है। सेबी के सर्कुलर में बीएसई और एनएसई को कारोबारी सीमा कम होने के बावजूद सोने और चांदी जैसी जिंसों में ऑप्शन शुरू करने की अनुमति दी गई है।'

कमोडिटी डेरिवेटिव्स में बड़ा सुधार

- नई व्यवस्था के तहत निपटान प्रक्रिया बेहद आसान है
- मौजूदा 'ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स' को बरकरार रखा जा सकेगा
- नए तरह का ऑप्शन कारोबार किसानों को हेजिंग के लिहाज से ज्यादा उपयुक्त
- एनसीडीईएक्स ने गेहूं, मक्का, मसालों में ऑप्शन कारोबार की योजना बनाई है

डार्क फाइबर मामले में रवि नारायण समेत नौ लोग आरोपमुक्त

बाजार नियामक सेबी ने 'संपर्क' को छूट देने में इन लोगों के खिलाफ नहीं पाया कोई साक्ष्य

बीएस संवाददाता और एजेंसियां
मुंबई, 16 जनवरी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नैशनल स्टॉक एक्सचेंज में हुए चर्चित डार्क फाइबर मामले में एक्सचेंज के पूर्व प्रमुख रवि नारायण समेत नौ लोगों को आरोपमुक्त करते हुए कहा है कि कुछ ब्रोकरों को अनुचित फायदा पहुंचाने में उनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई है।

सेबी ने आज जारी अपने बयान में कहा कि उसे किसी भी आरोपी की भूमिका साबित करने वाले कोई भी साक्ष्य या सामग्री नहीं मिली है। इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी 'संपर्क' की तरफ से पी2पी संपर्क मुहैया कराने के मामले में इन लोगों की संलिप्तता की तरफ इशारा करने वाले साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। सेबी ने मई 2019 में 'संपर्क' को अधिकृत लाइसेंस नहीं रखने वाले स्टॉक ब्रोकरों को डार्क फाइबर कनेक्टिविटी मुहैया कराने की इजाजत संपर्क को देने के लिए एनएसई और उसके दो पूर्व प्रमुख रवि नारायण एवं चित्रा रामकृष्ण पर जुर्माना लगाया था। डार्क फाइबर वह अप्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसका इस्तेमाल तीव्र गति वाली कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है।

इस मामले में नारायण और चित्रा के अलावा सात अन्य पदाधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल की गई। इनमें एनएसई के उपाध्यक्ष (परिचालन) आर नंदकुमार, कोलो प्रमुख जगदीश जोशी और मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ) एन मुरलीधरन एवं रवि आप्टे भी शामिल हैं। इन सभी को सेबी ने आरोपों से बरी कर दिया है। इनके अलावा एनएसई के मौजूदा मुख्य परिचालन अधिकारी (ट्रेडिंग) मयूर सिंधवाद, सीटीओ-प्रोजेक्ट संकर्षण बनर्जी, सीटीओ-परिचालन जी शेनॉय एवं उपाध्यक्ष-नियमन सुप्रभात लाला भी जांच में निर्दोष पाए गए हैं।

> उस समय यह आरोप लगा था कि एनएसई ने अपने सदस्यों के साथ निष्पक्ष एवं समान बर्ताव नहीं किया

एनएसई के इन मौजूदा एवं पूर्व अधिकारियों पर आरोप था कि अप्रैल-अगस्त 2015 के दौरान उनकी मिलीभगत से इंटरनेट सेवा प्रदाता 'संपर्क' ने कुछ ब्रोकरों को गोपनीय जानकारी मुहैया कराई जिससे उनके टर्नओवर में खासी बढ़ोतरी हुई। लेकिन पड़ताल के बाद सेबी ने पाया है कि इनमें से कोई भी अधिकारी अप्रैल-जुलाई 2015 के दौरान एनएसई में निदेशक या किसी अन्य महत्त्वपूर्ण पद पर नहीं आसीन था।

उस समय यह आरोप लगा था कि एनएसई ने अपने सदस्यों के साथ निष्पक्ष एवं समान बर्ताव नहीं किया और इस दौरान ये नौ अधिकारी एक्सचेंज के भीतर अहम पदों पर तैनात थे। इसी तरह एक्सचेंज में इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी को अपारदर्शी ढंग से विस्तार दिए जाने के मामले में भी सेबी को कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसी के साथ सेबी ने इन पदाधिकारियों के खिलाफ की गई फौरी कार्रवाई को भी निरस्त कर दिया है।

साउथ इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ 8 फीसदी बढ़ा

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 16 जनवरी

साउथ इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में 90.54 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि के 83.85 करोड़ रुपये के मुकाबले 8 फीसदी ज्यादा है।

सालाना आधार पर बैंक के कारोबार में 9 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई जबकि जमाओं (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को छोड़कर) में सालाना आदार पर 11 फीसदी का इजाफा हुआ। चालू-बचत खाते में इस अवधि में 13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई जबकि उधारी में 9 फीसदी का इजाफा हुआ।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी वी जी मैथ्यू ने कहा, बैंक ने 31 दिसंबर 2019 को 1.50 लाख रुपये के कुल कारोबार का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने कहा कि कर्ज के मामले में बैंक का ध्यान खुदरा, कृषि व एमएसएमई पोर्टफोलियो पर बना हुआ है और इन पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात एक साल पहले के 41.17 फीसदी से सुधरकर 50.37 फीसदी पर पहुंच गया।

कर्णाटक बैंक का लाभ घटा

कर्णाटक बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर के दौरान 12 प्रतिशत घटकर 123.14 करोड़ रुपये रहा। फंसा कर्ज बढ़ने से बैंक का लाभ कम हुआ है। बैंक ने कहा कि इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में उसे 140.41 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। हालांकि बैंक की कुल आय 2,023.68 करोड़ ररुपये रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1,815.79 करोड़ रुपये थी। बैंक की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी फंसा कर्ज आलोच्य तिमाही में बढ़कर 4.99 फीसदी पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 2018-19 की इसी तिमाही में 4.45 फीसदी था। बैंक का शुद्ध एनपीए भी बढ़कर 3.75 फीसदी हो गया। *भाषा*

2020 में बेहतर आय, उच्च रिटर्न पर विदेशी ब्रोकरेज का दांव

बीएनपी पारिबा ने एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स के लिए 44,500 का लक्ष्य तय किया है

सचिन मामबटा और समी मोडक
मुंबई, 16 जनवरी

विदेशी ब्रोकरेज साल 2020 में फंडामेंटल में सुधार और बाजार के सूचकांकों के और ऊपर जाने की संभावना जता रहे हैं, जो पहले ही सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है।

बीएनपी पारिबा सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट और मॉर्गन स्टैनली इंडिया ने अलग-अलग रिपोर्ट में तेजी का नजरिया जाहिर किया है। बीएनपी पारिबा ने एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स के लिए 44,500 का लक्ष्य तय किया है। गुरुवार को यह अब तक के सर्वोच्च स्तर 42,059.45 पर पहुंच गया। एक नोट में बीएनपी पारिबा ने कहा है कि बेंचमार्क भारतीय कंपनियों की आय में बढ़त का अनुमान अभी मार्च 2020 में समाप्त वर्ष के लिए 11 फीसदी है। वित्त वर्ष 2021 के लिए यह 19 फीसदी है।

बीएनपी पारिबा के इंडिया इक्विटी शोध प्रमुख अभिराम एलस्वरापू ने कहा है, हमें लगता है कि भारत की आय सुस्त बनी हुई है, लेकिन धारणा में सुधार से चुनिंदा शेयर खास तौर से अच्छी गुणवत्ता, बढ़त व मूल्यांकन वाले शेयर (मिडकैप व स्मॉलकैप समेत) में तेजी आ सकती है।

विदेशी ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली इंडिया भी कर कटौती, नकद हस्तांतरण जैसे नीतिगत सुधार की पृष्ठभूमि में उच्च बढ़त पर दांव लगा रही है। कंपनी की 15 जनवरी की रिपोर्ट में इक्विटी रणनीतिकार रिधम देसाई और शीला राठी ने ये बातें कही है इसमें कहा गया है, एक ओर जहां आय की रफ्तार सुधरेगी, वहीं हमारा यह भी मानना है कि नीतिगत कदम से ही बढ़त व शेयर की कीमतें साल 2020 में टिका रहना सुनिश्चित नहीं हो सकता।

बीएनपी पारिबा का मानना है कि सुदृढ़ बाजार का स्रोत देसी मसलों के बाहर हो सकता है, जो सुर्खियां बन रही हैं। यह दुनिया भर में नकदी की आसान स्थिति से संचालित हो सकता है। यह उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियों की ओर ले जाएगा क्योंकि निवेशक ज्यादा प्रतिफल चाहते हैं, जो भारत जैसे उभरते बाजार के लिए सकारात्मक है। यह इन देशों की मुद्राओं को भी बेहतर प्रदर्शन में मदद करेगा। बीएनपी पारिबा के मुताबिक, एशियाई बाजार अपनी मुद्राओं के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं।

उसे अमेरिका, यूरोप और ज्यादातर एशियाई क्षेत्रों में मौद्रिक व राजकोषीय सहजता की उम्मीद है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी कारोबार के दौरान अब तक के सर्वोच्च स्तर 12,389.05 अंक को छू गया।

फर्जी ईमेल से रहें सतर्क : बाजार नियामक सेबी ने पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों को फर्जी ई-मेल से सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि उसने रिफंड से जुड़े मामलों के लिए न तो किसी व्यक्ति को अधिकृत किया है और न ही कोई अधिकार पत्र जारी किया है। ई-मेल में कथित तौर पर सेबी द्वारा जारी अधिकार पत्र भी शामिल है और रिफंड से जुड़े मामले के लिए रवि शंकर आईएएस को नामित किया गया है। *भाषा*

फंड हाउस के लिए दुधारू गाय हैं बैंकिंग, वित्तीय शेयर

म्युचुअल फंडों ने बजट से पहले बैंकिंग व वित्तीय कंपनियों के शेयरों में निवेश बढ़ाया है। आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। आईसीआईसीआई बैंक में म्युचुअल फंडों के निवेश की वैल्यू दिसंबर में 2,900 करोड़ रुपये बढ़ गई। कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश की वैल्यू 1,320 करोड़ रुपये बढ़ी जबकि एचडीएफसी में 1,290 करोड़ रुपये और मारुति सुजूकी में निवेश की वैल्यू 1,200 करोड़ रुपये बढ़ी। भारती एयरटेल भी म्युचुअल फंडों की नजर में रही और इनके निवेश की कीमत 1,800 करोड़ रुपये बढ़ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज में म्युचुअल फंडों का निवेश 1,650 करोड़ रुपये बढ़ा है। निवेश में कमी वाली अन्य फर्मों में आईटीसी (1,050 करोड़ रुपये), एसबीआई (920 करोड़ रुपये) और बीपीसीएल (610 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

जश कृपलानी

म्युचुअल फंडों का निवेश बढ़ा

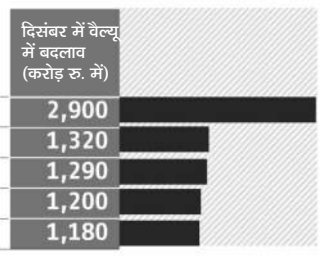

दिसंबर में वैल्यू में बदलाव

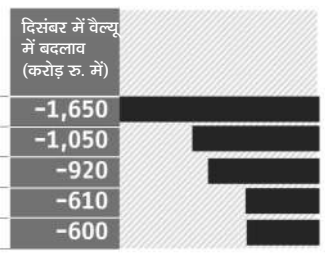

स्रोत : मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड

गोल्ड ईटीएफ पर पूंजीगत लाभ कर में राहत की मांग

लंबी अवधि के फायदे की गणना के लिए निवेशित अवधि घटाकर एक साल की जाए

जश कृपलानी
मुंबई, 16 जनवरी

म्युचुअल फंड उद्योग आगामी आम बजट में वित्त मंत्रालय से कई तरह की राहत मांग रहा है। इनमें जिंस व गोल्ड ईटीएफ में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के लिए निवेशित अवधि घटाना, इक्विटी व ईटीएफ में निवेशकों से वसूले जाने वाले प्रतिभूति लेनदेन कर को समाप्त करना और इक्विटी फंड के लिए सीमा पहले की तरह 50 फीसदी पर लाने की मांग शामिल है।

एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया ने 17 पन्नों की बजट मांग में कहा है, गोल्ड व कमोडिटी ईटीएफ को और आकर्षक बनाने की खातिर एलटीसीजी के मामले में निवेश की अवधि तीन साल से घटाकर एक साल किया जाना चाहिए, जैसा कि सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में होता है। गोल्ड व कमोडिटी ईटीएफ के लिए प्रस्तावों को छोड़कर उद्योग अपनी ज्यादातर मांग पहले भी कर चुका है। एम्फी के मुख्य कार्याधिकारी एन एस वेंकटेश ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस बार काफी समय से लंबित मांग पूरी होगी, जिससे भारतीय म्युचुअल फंड उद्योग को न सिर्फ बढ़त के अगले स्तर पर ले जाने में बल्कि अर्थव्यवस्था की मजबूती में योगदान में भी मदद मिलेगी।

म्युचुअल फंड उद्योग ने कहा कि इक्विटी म्युचुअल फंड योजनाओं और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के साथ अलग-अलग व्यवहार होता है जबकि दोनों निवेश योजनाएं हैं। उद्योग चाहता है कि इक्विटी म्युचुअल फंड योजनाओं को एलटीसीजी कर, प्रतिभूति लेनदेन कर और लाभांश वितरण कर से छूट मिले, जैसा कि यूलिप्स को मिलता है। रिटायरमेंट योजनाओं मसलन एनपीएस के समकक्ष एमएफ को रखने के लिए म्युचुअल फंड चाहता है कि धारा 89 सीसीडी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का विस्तार म्युचुअल फंडों की रिटायरमेंट व पेंशन योजना तक किया जाए।

उद्योग ने धारा 80 सीसीडी के तहत फायदों को अधिसूचित करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास वैयक्तिक रूप से आवेदन की अनिवार्यता से भी छूट मांगी है। उद्योग का कहना है कि सेबी से संपर्क कर सीबीडीटी खुद दिशानिर्देश का ढांचा तय कर म्युचुअल फंडों को म्युचुअल फंड लिंक्ड रिटायरमेंट प्लान पेश करने के लिए दे। डेट योजनाओं पर उद्योग ने लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर ठीक करने की मांग की है। उद्योग ने कहा है कि सूचीबद्ध ऋणपत्र में 12 महीने से ज्यादा निवेश को अभी भी लंबी अवधि का निवेश माना जाता है, वहीं अगर यह निवेश डेट योजनाओं के जरिए होता है तो लंबी अवधि के निवेश के लिए निवेशित अवधि 36 महीने मानी जाती है।

बदलाव की मांग

- एमएफ से जुड़ाव वाली रिटायरमेंट योजना को कर लाभ मिले
- डेट योजनाओं पर लाभांश वितरण कर घटे, कम से कम कंपनी कर की दर 22 फीसदी के बराबर हो
- एमएफ व यूलिप्स के बीच कर आर्बिट्रेज हटे

एयर एशिया के सीईओ तलब

एजेंसियां
नई दिल्ली, 16 जनवरी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारियों ने आज इसकी जानकारी दी।

कंपनी और उसके अधिकारियों पर 2018 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि फर्नांडीस को 20 जनवरी को तलब किया गया है। एयरलाइन के मौजूदा तथा पूर्व प्रबंधन के अन्य अधिकारियों को उसके बाद उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि जांच के लिए कुछ नए समन जारी किए गए हैं और एयरलाइन के अधिकारियों को मामले से संबंधित दस्तावेज साथ लाने के लिए कहा गया है। एयर एशिया पर आरोप है कि उसने अनुषंगी एयर एशिया इंडिया लिमिटेड को अंतरराष्ट्रीय मार्ग का लाइसेंस दिलाने के लिए सरकारी नीतियों को गलत तरीकों से प्रभावित करने की कोशिशें की हैं।

पीएलएमए के तहत ईडी ने मई 2018 में मामला दर्ज किया था, उसके दो दिन बाद इन आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने आपराधिक शिकायत दर्ज की।

इस आरोप के मद्देनजर सीबीआई की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ईडी ने जांच शुरू की। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत भी इस मामले में ईडी की भी जांच चल रही है।

एयर एशिया इंडिया की उड़ाने इस समय 21 घरेलू केंद्रों को जोड़ती हैं और एयरक्राफ्ट बेड़े पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक इसके बेड़े में 29 एयरबस ए-320 विमान शामिल हैं।

इस मामले में जांच की पहल टाटा समूह के चेयरमैन पद से हट चुके साइरस मिस्त्री के दावों के बाद की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाए गए थे कि 22 करोड़ रुपये का फर्जी लेन देन हुआ है, जिसमें भारत और सिंगापुर की अस्तित्व विहीन इकाइयां शामिल थीं।

सीबीआई और ईडी ने अपनी प्राथमिकियों में एयर एशिया समूह के सीईओ फर्नांडीस, एयर एशिया बरहाड समूह के पूर्व डिप्टी सीईओ तरुमलिंगम कनगलिंगम, जिन्हें बोलिंगम नाम से भी जाना जाता है और एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु के निदेशक आर वेंकटरमण को नामित किया है। प्राथमिकी में एयर एशिया और एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल किया गया है।

आरोप है कि एयर एशिया के अधिकारी व अन्य भ्रष्ट तरीकों से सरकार की नीतियों के साथ हेरफेर कर रहे थे, जिससे कि उनके भारतीय उद्यम एयर एशिया इंडिया लिमिटेड को अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस मिल सके।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वेंकटरमण आवश्यक मंजूरियों के पक्ष में सरकार के साथ गैर पारदर्शी तरीके से लॉबीइंग कर रहे थे। इसमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी, अनापत्ति प्रमाण पत्र और 5/20 नियमों को खत्म किया जाना या उसमें बदलाव शामिल है। अंतराष्ट्रीय परिचालन के लिए 5/20 नियमों के तहत कंपनी के पास 20 विमानों का बेड़ा और 5 साल का अनुभव जरूरी है।

एयर एशिया इंडिया लिमिटेड को अभी तक अंतरराष्ट्रीय उड़ान की मंजूरी नहीं मिली है। सीबीआई की शिखायत में आरोप लगाया गया है कि फर्नांडिज चाहते थे कि मई 2014 में उड़ान की अनुमति मिलने की तिथि से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ान की अनुमति मिल जाए। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वह और उनकी स्थानीय भारतीय साझेदार टाटा संस ने अपने नामित वेंकटरमनन के माध्यम से सरकार के साथ लॉबीइंग करने की कवायद की, जिससे एफआईपीबी मंजूरी मिल सके और मौजूदा 5/20 नियम में संशोधन या इसे खत्म किया जा सके और कंपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू कर सके।

सीबीआई ने कथित लॉबीयिस्ट के रूप में सिंगापुर की एचएनआर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेंद्र दुबे, टोटल फूड सर्विसेज, मुंबई के चेयरमैन सुनील कपूर, डीटीए कंसल्टिंग, नई दिल्ली के संस्थापक और प्रमुख दीपक तलवार (जिसे पिछले साल दुबई से भारत भेज दिया गया है) और एचएनआर ट्रेडिंग को भी नामित किया है, जिन्होंने 2014 में हुए आम चुनाव के पहले 5/20 नियम के मानकों में ढील के लिए अपने प्रभाव का कथित रूप से इस्तेमाल किया।

जांच में आई तेजी

सीबीआई और ईडी ने फर्नांडीस के साथ एयर एशिया बरहाड समूह के पूर्व डिप्टी सीईओ तरुमलिंगम कनगलिंगम और एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु के निदेशक आर वेंकटरमण को नामित किया

20 जनवरी को ईडी द्वारा तलब किए गए टोनी फर्नांडिज

21 घरेलू केंद्रों पर विमान सेवा दे रही कंपनी

- 5/20 नियम में संशोधन या इसे खत्म करने व एफआईपीबी की मंजूरी के लिए लॉबीयिंग का आरोप
- साइरस मिस्त्री के 22 करोड़ रुपये फर्जी लेने देन के दावों के बाद शुरू हुई थी जांच

अदाणी एंटरप्राइजेज और एनसीसीएफ के पूर्व प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 16 जनवरी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश की बिजली कंपनी को आयातित कोयले की आपूर्ति के ठेके के आवंटन में कथित अनियमितता, आपराधिक षडयंत्र और भ्रष्टाचार के मामले में आज गौतम अदाणी की कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज और नैशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया (एनसीसीएफ) के दो पूर्व शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

यह मामला 2010 का है, जब आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन (एपीजीईएनसीओ) ने फ्री-ऑन-रेल डेस्टिनेशन के आधार पर डॉ नारला टाटा राव थर्मल पॉवर स्टेशन विजयवाड़ा और रायलसीमा थर्मल पॉवर प्लांट कडपा में किसी भी बंदरगाह से 6 लाख टन कोयले की आपूर्ति के लिए निविदा जारी की थी।

निविदा की सूचना के बाद एनसीसीएफ ने इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी इकाइयों से बोली मांगी। इसी साल जुलाई में एनसीसीएफ ने 6 बोलीकर्ताओं- अदाणी इंटरप्राइज, व्योम ट्रेड लिंक्स, माहेश्वरी ब्रदर्स, कोल स्वर्ण प्रोजेक्ट्स, गुप्ता कोल इंडिया और क्योरी ओरेमेन से बोली हासिल की।

बोली लगाने वाली 6 कंपनियों में से सिर्फ 3 ने ही एनसीसीएफ के मार्जिन के मुताबिक बोली लगाई, जिसे एनसीसीएफ के दिल्ली कार्यालय ने रद्द कर दिया क्योंकि यह पाया गया कि वे निविदा की शर्तें नहीं पूरी करतीं। वहीं अदाणी सहित 3 ने कोई मार्जिन कोट नहीं किया था।

अदाणी एंटरप्राइजेज की बोली रद्द करने के बजाय एनसीसीएफ के शीर्ष प्रबंधन ने एनसीसीएफ के ऑफर मार्जिन की सूचना कंपनी को अपने प्रतिनिधि मुनीश सहगल के माध्यम से दी, जो कथित रूप से उसी शाम एनसीसीएफ के कार्यालय में बैठे थे और उसके बाद अदाणी ने एनसीसीएफ के शाखा प्रबंधक को सूचित किया कि कंपनी 2.25 प्रतिशत की दर पर एनसीसीएफ को प्रीमियम सर्विस/शुल्क भुगतान करने को सहमत है। सीबीआई की जांच में पाया गया कि टेंडर के बाद एनसीसीएफ के अधिकारियों द्वारा अदाणी एंटरप्राइजेज का पक्ष लेने के लिए बातचीत की गई और सीबीआई ने कहा है कि उसने (अदाणी) हैदराबाद में टेंडर खोले जाते समय शर्तें नहीं पूरी की थी।

सीबीआई की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि एनसीसीएफ, नई दिल्ली के तत्कालीन चेयरमैन वीरेंद्र सिंह और उस समय एनसीसीएफ के प्रबंध निदेशक जीपी गुप्ता ने ठेका देने में अदाणी एंटरप्राइजेज का पक्ष लिया।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि जब बोली की प्रक्रिया एनसीसीएफ के मुख्यालय में चल रही थी, अदाणी एंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि को सूचित किया गया कि उन बोलीकर्ताओं को खारिज कर दिया गया है, जिन्होंने एनसीएफ मार्जिन कोट नहीं दाखिल किया है और साथ ही यह भी बताया गया कि माहेश्वरी ब्रदर्स ने 2.25 प्रतिशत मार्जिन कोट किया है।'

सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने टेंडर नोटिस में तय की गई 2 अहम शर्तों की उपेक्षा की और अदाणी एंटरप्राइजेज को अयोग्य घोषित करने के बताय उसका पक्ष लिया। माहेश्वरी और अदाणी को ठेका देने का पूरा फैसला शीर्ष प्रबंधन द्वारा किया गया। सीबीआई रिपोर्ट में अदाणी एंटरप्राइजेज और व्योम के बीच संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक अदाणी एंटरप्राइजेज ने बोली लगाने वाली 6 कंपनियों में से एक व्योम ट्रेड को 16.81 करोड़ रुपये का असुरक्षित कर्ज दिया था।

कोयले की कालिख

- मामला 2010 में ताप बिजली संयंत्रों को आयातित कोयले की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है
- 6 कंपनियों ने लगाई थी कोयले की आपूर्ति के लिए बोली, एनसीसीएफ के अधिकारियों पर अदाणी एंटरप्राइजेज का पक्ष लेने का आरोप

महंगाई क्षणिक, सुधरेगी स्थिति

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 16 जनवरी

भारत में महंगाई दर दिसंबर महीने में 5.5 साल के उच्च स्तर 7.35 प्रतिशत पर पहुंच गई है, आर्थिक वृद्धि दर 5 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है, वहीं केंद्र सरकार का मानना है कि यह क्षणिक है और आने वाले महीनों में स्थिति सुधर जाएगी। सरकार का मानना है कि हाल के कुछ महीनों में उठाए गए कदमों और महंगाई और वृद्धि दर में गिरावट को रोकने की उसकी कवायदों से स्थिति करीब सामान्य हो जाएगी। विभिन्न उद्योग संगठनों की ओर से आयोजित संयुक्त आयोजन में वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 'अभी चल रही महंगाई क्षणिक है और मौसम में बदलाव के साथ स्थिति सुधरेगी।'

विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगी और कर रियायत!

पृष्ठ 1 का शेष

इन्वेस्ट इंडिया ने कहा कि प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और वित्त मंत्री से इन कंपनियों को भी रियायती कर दायरे में लाने की मांग की जाएगी। अधिकारी ने कहा, 'यह वित्त मंत्रालय पर निर्भर करेगा कि वह अप्रैल 2019 या अगस्त 2019 से कंपनियों के लिए रियायती कर दर की अनुमति देता है या नहीं। लेकिन यह वास्तविक चिंता का विषय है।' नांगिया एंडरसन कंसल्टिंग के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि सरकार को उद्योग के सुझाव पर विचार करना चाहिए और 1 अपगैल, 2019 से लगाई गई विनिर्माण इकाइयों के लिए भी नई दरें लागू करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर की दर में कटौती अच्छी पहल है लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, 'मांग और निवेश चक्र में सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है, जिससे रोजगार का भी सृजन होगा।'

राघवेंद्र बैंक के जमाकर्ता नहीं जाएंगे न्यायालय

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 16 जनवरी

श्री गुरु राघवेंद्र सहकार बैंक के जमाकर्ताओं ने राहत के लिए न्यायालय न जाने का फैसला किया है क्योंकि बैंक ने कहा है कि वह इस साल 31 मार्च तक सभी प्रतिबद्धताएं पूरी करने में सक्षम होगा। जमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति ने कहा, 'हम न्यायालय जाने को इच्छुक नहीं हैं क्योंकि इससे हमें प्रक्रिया में देरी का डर है। इसके बजाय हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पैसा वापस मिलेगा क्योंकि प्रबंधन कह रहा है कि प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की बात कही है।' भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 जनवरी को अधिसूचना जारी कर नियामक बैंक की मंजूरी के बगैर बैंक को धन जमा करने, नया कर्ज देने या निवेश करने पर रोक लगा दी थी।

यूनिटेक को संकट से उबारना मंत्रालय का लक्ष्य

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 16 जनवरी

कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने रियल एस्टेट की संकटग्रस्त कंपनी यूनिटेक को संकट से बाहर निकालने के लिए एक वृहद रणनीति तैयार की है। इसके लिए उसने दस सदस्यों का एक नया निदेशक मंडल तैयार किया है जिसमें वित्तीय और तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ और एक प्रसिद्ध उद्योपति शामिल है।

बुधवार को एमसीए ने संकट में घिरी कंपनी यूनिटेक का प्रबंधन हासिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रस्ताव जमा कराया। सरकार ने कहा है कि वह कंपनी में कोई निवेश नहीं करेगी। इसके बजाय वह घर खरीदारों की बची हुई किस्तों के जरिये निमार्णाधीन आवासीय परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराएगी। बोर्ड यूनिटेक की ऐसी संपत्तियों का मुद्रीकरण का प्रयास भी करेगा जिसे फिलहाल गिरबी नहीं रखा गया है।

इसके अलावा एमसीए को पता चला है कि यूनिटेक को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से 300-400 करोड़ रुपये तक की रकम मिलनी है जिसका इस्तेमाल वह आवासीय मकानों के निर्माण को पूरा करने में करेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हमें इस कंपनी को चालू हालत में बनाए रखने की जरूरत है। आवासीय इकाइयों का काम पूरा करना सबसे प्राथमिक चिंता है।'

निर्माण के ठेके देने का निर्णय बोर्ड लेगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'हम कंपनी का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की बात कह रहे है, कंपनी लेने की नहीं।'

यूनिटेक की फंसी हुई परियोजनाओं के कारण 16,000 घर खरीदार प्रभावित हुए थे जिनमें से 4,700 खरीदार अपना पूरा पैसा वापस पाना चाहते थे जबकि अन्य 9,400 खरीदारों ने पैसा रिफंड किए जाने या फिर फ्लैट देने की बात कही थी।

हालांकि सरकार के प्रस्ताव में रिफंड का प्रावधान नहीं है। एमसीए ने सर्वोच्च न्यायालय से सरकार की ओर से गठित किए गए बोर्ड को यूनीटेक की तरफ से किसी भी कानूनी कार्रवाई से वैधानिक प्रतिरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की है। इसकी वजह है कि यूनिटेक के निदेशकों ने बैंक ऋणों पर ऋण स्थगन की मांग की थी।

पिछले वर्ष मई में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को संकट में फंसी रियल्टी फर्म को अपने हाथों में लेकर उसकी अटकी परियोजनाओं को पूरा करने की संभावना तलाशने के लिए कहा था ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके। न्यायालय ने यह निर्णय वित्त या रियल एस्टेट में विशेषज्ञता नहीं होने के कारण लिया था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाले दो न्यायाधिशों के पीठ ने महान्यायवादी के के वेणुगोपाल को इस मामले में अपनी सहायता देने के लिए कहा था। न्यायालय ने उन्हें सरकार के एक उचित स्तर पर बैठक कर इस पर विचार करने के लिए कहा था कि क्या यूनिटेक की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इसे किसी सरकारी कंपनी को सौंपा जा सकता है।

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और उसका भाई अजय चंद्रा अगस्त 2017 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर कथित तौर पर घर खरीदारों का पैसा गबन करने का आरोप है। चंद्रा भाइयों को अप्रैल 2017 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। उन पर कंपनी के ग्रेटर नोएडा की आवासीय परियोजना में 35 करोड़ रुपये का फ्टैल बुक कराने वाले खरीदारों के साथ घोखा करने का आरोप था।

यूनिटेक के लिए सरकार का प्रस्ताव

- सरकार ने रियल एस्टेट की संकटग्रस्त कंपनी यूनिटेक को संकट से बाहर निकालने के लिए एक वृहत रणनीति बनाई
- मंत्रालय ने कंपनी के लिए दस सदस्यों का एक नया निदेशक मंडल बनाया
- सरकार घर खरीदारों की बची हुई किस्तों से निमार्णाधीन आवासीय परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराएगी
- यूनिटेक की फंसी परियोजनाओं में16,000 घर खरीदार प्रभावित हुए थे

सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर संरक्षण शुल्क लगा सकती है सरकार

शुभायन चक्रवर्ती और अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 16 जनवरी

सरकार सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर 25 प्रतिशत संरक्षण शुल्क लगा सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक इस सिलसिले में अधिसूचना जल्द आने की संभावना है।

पिछले साल स्टरलाइट टेक्नोलॉजिज और बिड़ला फुरुकावा फाइबर जैसी कंपनियों ने कारोबारी उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के पास आवेदन दाखिल कर फाइबर पर संरक्षण शुल्क लगाए जाने की मांग की थी। 2018-19 में इस श्रेणी में आयात 3 गुना बढ़कर 18 करोड़ डॉलर हो गया, जो इसके पहले के साल में महज 5.13 करोड़ डॉलर था। सरकार के भारतनेट कार्यक्रम के लिए फाइबर की सरकारी खरीद के कारण अचानक यह तेजी आई है।

नवंबर में डीजीटीआर ने अस्थायी रूप से 200 दिन के लिए 25 प्रतिशत संरक्षण शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया था। यह पाया गया था कि खासकर चीन से सस्ता आयात हो रहा है, साथ ही दक्षिण कोरिया और जापान भी भारतीय बाजारों में माल उतार रहे हैं, उसके बाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव आया। सस्ते आयात की वजह से पिछले वित्त वर्ष में भारत की घरेलू कंपनियों को कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी और उन्हें अपनी विनिर्माण इकाइयां बंद करनी पड़ी। मांग में बढ़ोतरी के बावजूद 2018-19 में फर्मों के क्षमता उपयोग के साथ मुनाफे और बाजार हिस्सेदारी में भी कमी आई।

सरकार के निष्कर्षों पर जनता की प्रतिक्रिया मिलने के 21 दिन बाद उम्मीद की जा रही थी कि सरकार कार्रवाई करेगी। यह अवधि अब खत्म हो गई है।

ज्यादा दाम के अन्य सामानों में शामिल सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर केबल के विनिर्माण के लिए होता है। यह आयात सरकार की नजर में था क्योंकि इस तरह के केबल का इस्तेमाल खासकर महत्त्वाकांक्षी भारतनेट कार्यक्रम में होता है, जो 2017 में शुरू किया गया है। भारतनेट के तहत एक नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना है, जिसके माध्यम से 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सभी परिवारों व संस्थानों को देश भर में मिल सके।

ऑप्टिकल केबल से डिजिटल डेटा सिगनल की सैकड़ों मील तक आवाजाही होती है, जिसकी प्रवाह क्षमता की दर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन केबल की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। इसमें बाल की तरह पतले पारदर्शी सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, जो कम अपवर्तक इंडेक्स्ड क्लैडिंग से ढके होते हैं, जिससे आसपास लाइट लीकेज को रोका जा सके। ऑप्टिकल फाइबर के बहुत ज्यादा संवेदनशील होने के कारण यह सामान्यतया ज्यादा मजबूत, हल्की रक्षात्मक सामग्री जेसे केवलर से ढका होता है।

यही वजह है कि ज्यादा खर्चीला होने के बावजूद राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) ने ऑप्टिकल फाइबर अपनाने का फैसला किया। एनओएफएन का मकसद देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से हर पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ना और न्यूनतम 100 एमबीपीएस की स्पीड प्रदान करना है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बीएसएनएल, रेलटेल और पावरग्रिड के मौजूदा फाइबर केबल का इस्तेमाल हो रहा है और इसकी पहुंच बढ़ाई जा रही है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार की योजना आयात शुल्क बढ़ाने की है, जिससे घरेलू विनिर्माताओं को राहत मिलेगी, लेकिन हमसे यह भी कहा गया है कि एनओएफएन जैसी मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर इसका असर पड़ सकता है क्योंकि मौजूदा घरेलू विनिर्माण क्षमता कम है।

कम समय में घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत फाइबर केबल के उत्पादन पर अतिरिक्त प्रोत्साहनों की भी घोषणा कर सकती है।

इस योजना से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि केबल बिछाने के लिए राह निकालना भी अब बड़ी चुनौती है क्योंकि नगर निगम और ग्राम पंचायतें अक्सर केबल बिछाने के काम को अनुमति नहीं देतीं, जो उनकी जमीन से होकर गुजरता है। इस तरह की समस्या का सामना बिजली या जलनिकासी लाइनों के मामले में नहीं उठती है क्योंकि लोगों को इसका सीधा लाभ नजर आता है। इसकी वजह से इस उद्योग ने सरकार से इसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र में डालने की मांग की है, जिससे कि इस क्षेत्र को सरकार का जरूरी समर्थन मिल सके।

अधिसूचना जल्द

- 25 प्रतिशत संरक्षण शुल्क लगाने की अधिसूचना जल्द आने की संभावना
- 2018019 में पिछले साल की तुलना में 3 गुना बढ़कर 18 करोड़ डॉलर हो गया है आयात
- भारत में इसका उत्पादन कम होने की वजह से भारतनेट जैसे कार्यक्रमों पर असर की भी चिंता

बीएस सूडोकू 3641

			1	7			3	
6		1	4		5	9		
	9	4			3		1	5
							2	1
		7		9		3		
4	8							
1	7		3			2	9	
		3	9		2	6		7
	4			6	8			

परिणाम संख्या 3640

1	6	4	2	8	7	9	5	3
2	5	3	9	6	4	7	1	8
9	8	7	5	1	3	2	4	6
6	4	5	1	7	2	8	3	9
3	9	2	8	5	6	1	7	4
7	1	8	4	3	9	6	2	5
5	2	1	3	9	8	4	6	7
8	3	6	7	4	1	5	9	2
4	7	9	6	2	5	3	8	1

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान
★☆☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2170/2180, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4650/4700, तिल सफेद 9000/9200, सोया (टीन) 1550/1600, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1475/1575,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2170/2180, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3350, चावल (सोना) 2900/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1430, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1505, फ्लैक 1450, डीएमओ 1043, टरपीन लेस बोल्ड 1516

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1200/1300, खुरपा 1080/1120,चाकू 1030/1150, रसकट 930/945, शक्कर 1280/1300, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3370, सिहोरा 3300, बुंदकी 3310, बुढ़ाना 3390,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1100/1110, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4400, खल: सरसों 2200/2300, बिनौला 2450/2600, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2250/2260, मक्की 2250/2275, बाजरा 1940/1945, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3800/3850, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4490/4500,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2140/2150, ग्वार 3800/3850, जौ 2140/2150,

जोधपुर
गेहूं 2150/2200, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4600/4700, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4000/4050, ग्वारगम 7400/7450, बाजरा (गुजरात) 1900/1925, बाजरा (जयपुर) 1900/1925, चना 4300/4350, काबली चना 5000/6000, मूंग 6800/6900,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)127, राइसब्रान (अखाद्य) 124, खल सरसों 2050, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1250, कंटीन्यूअस 1325,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7800/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7500/8500, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8800/9500, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5700/5800, शरबती साधारण सेला 3800/3850, शरबती स्टीम 4200/4250,चावल 1509 सेला 4900/4950, धान: शरबती 2000/2050,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4085/4115, हरियाणा 4060/4080, राजस्थान 4050/4100, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2550/2650, सरसों खल 2150/2180,

फाजिल्का
गेहूं 2220/2230, सरसों 4400/4425 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4170/4180, कपास देशी 5150/5225, कपास नरमा (क्विं.) 5300/5400, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2650/2700,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2220/2230, चावल परमल कच्चा 2400/2425, से ला 2350/2375, मक्की यूपी 2175/2200, दाल उड़द छिलका 9200/10400, चना देशी 5000/5100, दाल चना 5300/5400, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7200/8600, चीन 8000/8500,

करनाल
गेहूं दड़ा 2190/2200, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2950/3000, पूसा 1509 धान 2850/2875, शरबती धान 2100/2150, सेला (1509 नं.) चावल 5175/5200, स्टीम 6050/6150,

हिसार
ग्वार 3800/3825, जौ 1800/1810, सरसों 4100/4150, मूंग 6800/7000, गेहूं 2180/2190,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1080/1090, मैदा 1190/1200, देशी घी (एक ली/जार) 400/500, रिफाइंड (टीन) 1600/1620,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4200/4250, खल बिनौला मोटी 2300/2400, बिनौला 2700/3200, सरसों तेल 9150/9200, गेहूं 2200/2225, ग्वार 3800/3850, बाजरा 1850/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 285

विचारणीय टिप्पणी

इस सप्ताह न्यूयॉर्क में माइक्रोसॉफ्ट के एक आयोजन में सॉफ्टवेयर क्षेत्र की इस आला कंपनी के भारतीय मूल के मुख्य कार्याधिकारी अधिकारी (सीईओ) सत्य नाडेला की बातों पर विवाद हो गया। नाडेला के बारे में कहा गया कि उन्होंने नए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को 'दुखद' और 'खराब' बताया। सोशल मीडिया पर तथा अन्य जगहों पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसके बाद कंपनी के भारत स्थित कार्यालय को नाडेला के वक्तव्य को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। नाडेला ने अमेरिका में एक आप्रवासी के रूप में अपने सुखद अनुभव की बात की थी और कहा था कि वह अपनी जन्मभूमि में भी ऐसा ही चाहते हैं। नाडेला ने कहा था, 'मुझे अच्छा लगेगा यदि कोई बांग्लादेशी आप्रवासी भारत आकर वहां 100 अरब डॉलर मूल्य की कंपनी खड़ी करता है या इन्फोसिस का अगला सीईओ बनता है। ऐसी आकांक्षा होनी चाहिए। मेरे साथ जो अमेरिका में हुआ, वही भारत में होना चाहिए।'

नाडेला ने अपने नजरिये में जो साफगोई दिखाई है वह तारीफ करने लायक है। वह जिस भारत की बात कर रहे हैं वह एक ऐसा देश होगा जहां महत्त्वाकांक्षी और आकांक्षी लोगों का स्वागत तो होगा ही बल्कि ऐसी महत्त्वाकांक्षा को पुरस्कृत भी किया जाएगा। यह सफलता न केवल व्यक्तिगत रूप से तकदीर बदलने वाली होगी बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर आम सहमति है कि आप्रवासन से देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। भले ही यह अत्यंत कम कुशलता वाले कर्मियों का आप्रवासन हो। भारत के अलावा अमेरिका में भी फिलहाल यह बहस चल रही है। यह भी एक वजह है जिसके चलते नाडेला अपने अनुभवों के बारे में बात करने को विवश हुए। इसके अलावा यह भी सही है कि आप्रवासन को लेकर देश की मौजूदा व्यवस्था और इसे तथा सीएए को लेकर हो रही बहस बुनियादी रूप से उस राह से अलग हैं जो देश की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है और जो किसी भी उदार लोकतंत्र को अपनानी चाहिए। असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) जैसा कोई अन्य दु:स्वप्न नहीं घटित होना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि एक अद्यतन, धार्मिक दृष्टि से निरपेक्ष और किफायती आप्रवासन व्यवस्था लागू की जाए। आप्रवासियों को नागरिकता देने का एक तरीका होना चाहिए, अस्थायी वर्क परमिट की गुंजाइश होनी चाहिए और कागजी कार्रवाई कम होनी चाहिए। फिलहाल भारतीय नागरिकता हासिल करना या ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड की पात्रता न रखने वाले लोगों के लिए वर्क परमिट हासिल करना अत्यंत कठिन है। विश्व शक्ति बनने की आकांक्षा रखने और दुनिया भर से प्रतिभाओं को अपने पास जुटाने की इच्छा रखने वाला कोई देश ऐसी व्यवस्था जारी नहीं रख सकता। दुनिया भर में प्रतिभाओं को लेकर जंग छिड़ी हुई है। तमाम दुनिया के देश और शहर यह समझ रहे हैं कि आने वाले दशकों में आर्थिक वृद्धि नवाचार, उद्यमिता और रचनात्मक पर केंद्रित होगी। भारत इस होड़ से बाहर नहीं रह सकता।

सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि यदि वह नाडेला की भावनाओं से सहमत नहीं भी होती तो भी भारत समेत दुनिया के तमाम निवेशक और कारोबारी इससे इत्तफाक रखते हैं। किसी भी देश में समुचित निवेश माहौल के लिए सामाजिक स्थिरता एक पूर्व शर्त की तरह है। अब तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सीएए, एनआरसी और सामाजिक मोर्चे पर सरकार के ऐसे अन्य कदम सामाजिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाते हैं और इनके गहन आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं। नाडेला तथा उनकी जैसी हैसियत वाले अन्य लोग सरकार से यही चाहेंगे कि वह ऐसे कदमों के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करे।

बिनय सिन्हा

बहुसंख्यकवादी एजेंडे से कमजोर होगा देश

सत्ता प्रतिष्ठान का नेतृत्व करने वालों को यह समझना होगा कि उनकी विभाजनकारी नीतियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर रही हैं और वे देश की बेहतरी के लिए कितनी नुकसानदेह हैं। बता रहे हैं श्याम सरन

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ गत 5 जनवरी को जो हिंसा की गई, उसे अंजाम देने वालों ने भले ही नकाब पहन रखे थे लेकिन उनका राजनीतिक और वैचारिक रुझान छिप नहीं सका। दरअसल यह हमला शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज और अल्पसंख्यकों को सोचा समझा संदेश था कि यदि वे भारतीय राज्य और समाज के नए बन रहे बहुसंख्यक ढांचे का विरोध करेंगे तो उनका यही हश्र किया जाएगा। जेएनयू में जो हुआ वह पहले जामिया और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में घटी घटनाओं का विस्तार था। जामिया और अलीगढ़ के बाद इन घटनाओं ने समूचे उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध करने वालों से बदला लिया जाएगा। इन सभी घटनाओं में यह देखा गया कि लोगों की संपत्ति और उनके जीवन की रक्षा के लिए बनी सरकारी मशीनरी हिंसा भड़कने पर खामोश बनी रही। खासकर उन लोगों के खिलाफ हुई हिंसा में जो सत्ता के वैचारिक और राजनीतिक एजेंडे के खिलाफ हैं। असहमति को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया में एक तरह की निष्ठुरता देखने को मिली जो परेशान करने वाली है। हालिया अतीत में हमने देखा है कि इस तरह का ध्रुवीकरण राजनीतिक लाभ दिला सकता है। परंतु यह एक खतरनाक खेल है जो देश के भविष्य पर बुरा असर डाल सकता है।

धार्मिक और वैचारिक आधार पर हो रहा ध्रुवीकरण अक्सर एक दूसरे में गुंथ जाता है। मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग और वाम धड़े को एक साथ राष्ट्रीय हित के खिलाफ माना जा रहा है। जामिया और एएमयू में और बाद में समूचे उत्तर प्रदेश और जेएनयू में जिस तरह कानून व्यवस्था कायम करने वाली मशीनरी का रुख समझौतापरक रहा वह आगे चलकर मोदी सरकार के समक्ष प्रतिरोध बढ़ाएगी। गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसा प्रतिरोध जोर पकड़ेगा। यह हो रहा है और सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि वह इस समस्या से समझदारी से निपटे। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो इससे विपक्ष का विस्तार होगा और कुछ तत्त्व प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसा का सहारा भी ले सकते हैं। तब सुरक्षा की दृष्टि से बल प्रयोग बढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा। इस दौरान नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर भी रोक लगेगी। खतरा यह है कि इस प्रक्रिया में देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। यदि असहमति और हिंसा इसी प्रकार बढ़ती रही तो यह एक बड़ी त्रासदी होगी। इससे हिंसा बढ़ेगी और देश बाहरी ताकतों के समक्ष कमजोर पड़ेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अतीत में चीन ने पूर्वोत्तर की अशांति का इस्तेमाल करते हुए भारत की सुरक्षा को कमजोर किया। पाकिस्तान ने पंजाब और कश्मीर में राजनीतिक अशांति का लाभ लिया। यदि देश के हृदयस्थल में राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। सीमाओं की सुरक्षा की चुनौती तब और बढ़ेगी।

वाम चरमपंथ से निपटने का उदाहरण भी हमारे सामने है जहां राज्य सत्ता द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद केवल सीमित सफलता हासिल हुई। राज्य द्वारा हथियारबंद दमन हिंसा फैलाने वालों तक ही सीमित नहीं रहता। अपनी प्रकृति के अनुसार ही यह एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेता है। इससे हिंसक प्रतिरोध कम होने के बजाय बढ़ता है। ऐसी अशांति को खत्म करने के लिए हमेशा संवाद ही काम आया है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही संभव हुआ।

जम्मू कश्मीर का संवैधानिक दर्जा बदलने के बाद लगातार छठे महीने एक तरह की बंदी लागू है। ऐसे में देश के अन्य हिस्सों में संभावित घटनाक्रम को लेकर सचेत होने की आवश्यकता है। असंतोष को वैमनस्य में बदलने देना समझदारी नहीं होगा।

सरकार के भीतर यह अनकहा भरोसा विद्यमान है कि उसके बहुसंख्यकवादी एजेंडे का अंतरराष्ट्रीय नीति पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत एक बड़ी शक्ति और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश है। वह अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों जगह आलोचना करने वाली आवाज को खामोश करने की ताकत रखता है। यह भरोसा गलत है। पहली बात तो यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था को राजनीतिक उथलपुथल से बचाया नहीं जा सकता है। अल्पसंख्यकों की बढ़ती नाराजी और क्रोध इस पर अपना असर डालेंगे। अर्थव्यवस्था की मौजूदा मंदी देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ती अशांति के असर में और गंभीर होगी। ऐसे में विदेशी निवेशकों के रुझान पर नकारात्मक असर होगा। ऐसे में हमारे लिए कूटनयिक गुंजाइश भी कम होगी।

भारत ने बीते सात दशक में बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी विविधतापूर्ण लोकतंत्र के रूप में जो राजनीतिक पूंजी जुटाई है उसके लिए भी कतई सराहना की कोई भावना नहीं है। व्यापक आर्थिक और सैन्य क्षमताओं से जो क्षमता हासिल हुई है उसे बल प्रदान करने का काम हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव करता है। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के आरंभ के बाद घटी घटनाओं जिनमें कश्मीर का संवैधानिक दर्जा बदलना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संबंधी निर्णय और अब सीएए शामिल है, ने देश के बाहर एक नकारात्मक अवधारणा बनाने का काम किया है। जेएनयू जैसी घटनाएं इस छवि को और बिगाड़ेंगी। दूसरे देशों के नागरिक समाज और मीडिया से भारत पर दबाव आ सकता है। इसके साथ ही वे हमारे मित्र और शत्रु देशों की सरकारों को यह अवसर प्रदान करेंगी कि वे भारत की कीमत पर लाभ ले सकें। इससे भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा।

एक विभाजित देश, असुरक्षित भी होता है। जबकि विविध लोगों से बना एकजुट देश एक समावेशी राष्ट्र का निर्माण करता है। मौजूदा राजनीतिक प्रतिष्ठान के नेतृत्वकर्ता चाहे वे केंद्र के हों या राज्य के, उन्हें यह समझना होगा कि उनकी विभाजनकारी नीतियां देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और बेहतरी के खिलाफ खतरनाक हो सकती हैं। उन्हें यह समझना होगा कि उनकी नीतियां देश के अल्पसंख्यकों, नागरिक समाज और कारोबारी जगत के मन में गहरा भय और आशंका पैदा कर रही हैं। सरकार को उन्हें आश्वस्त करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो भारत धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था से निपटने और जटिल और तेजी से बदलते भूराजनीतिक परिदृश्य में प्रभावी नहीं रह जाएगा।

(लेखक पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं)

आम बजट : कृषि क्षेत्र के लिए सरकार को क्या करना चाहिए ?

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

क्या केंद्र सरकार कृषि पर पर्याप्त खर्च कर रही है? आम बजट से पहले यह सवाल फिर सुर्खियों में है। खासकर, इसलिए क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा संसाधनों के आवंटन की मांग की जा रही है। इसके पीछे यह सोच है कि कृषि पर व्यय बढ़ने से भारतीय किसानों के हाथों में खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी और मांग बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटेगी। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए?

पिछले कई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्रियों ने भाषणों में किसानों के कल्याण के वास्ते बड़ी-बड़ी बातें कीं लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए बजट का पर्याप्त आवंटन नहीं किया। उदाहरण के लिए 2017-18 का ही बजट लीजिए जिसके लिए अंकेक्षित आंकड़े उपलब्ध हैं। इसमें करीब एक दर्जन पैराग्राफ किसानों को समर्पित थे। लेकिन पिछले साल जुलाई में जारी 'बजट: एक नजर' दस्तावेज के मुताबिक कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर कुल 52,628 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है जो 2017-18 में सरकार के कुल व्यय का महज 2.45 फीसदी है।

फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की घोषणा के बाद इसमें थोड़ा अंतर आया है। 2019-20 के अंतरिम बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी और इसके तहत दो हेक्टेयर से कम जोत वाले सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये नकद देने का वादा किया गया था। इस योजना को पिछली तारीख से 1 दिसंबर, 2018 से लागू किया गया और देश में करीब 86 फीसदी कृषि योग्य भूमि इसके दायरे में हैं।

कृषि और संबंधित गतिविधियों पर सरकार का खर्च 2018-19 में बढ़कर 86,602 करोड़ रुपये पहुंच गया जो उस साल सरकार के कुल खर्च का 3.5 फीसदी था। अगर इसमें से पीएम-किसान की राशि को हटा दें तो कृषि क्षेत्र पर सरकारी व्यय केवल 66,602 करोड़ रुपये यानी सरकार के कुल खर्च का महज 2.7 फीसदी था।

2019-20 में पूरे साल के लिए पीएम-किसान योजना की राशि दी गई जिससे कृषि और संबंधित गतिविधियों पर सरकार का खर्च बढ़कर 1.51 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया जो कुल सरकारी खर्च का करीब 5.4 फीसदी है। उल्लेखनीय है कि इसमें से करीब आधी राशि (75,000 करोड़ रुपये) पीएम-किसान के हिस्से की थी। सरकार ने अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर सभी किसानों को इसमें शामिल कर लिया है जिससे इसका वार्षिक व्यय बढ़कर 89,000 करोड़ रुपये पहुंचने की संभावना है।

कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर सरकारी खर्च में पीएम-किसान की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। संभवत: हाल के वर्षों में यह किसानों के लिए सबसे बड़ी बजट घोषणा थी। किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष नकदी अंतरण कृषि पर खर्च का सबसे जरिया बन गया है।

शायद यही आगे का रास्ता है। किसानों को प्रत्यक्ष नकदी अंतरण के तहत ज्यादा राशि दीजिए और उन्हें ही यह करने दीजिए कि इसे कहां और कैसे खर्च करना है। यह ग्रामीण भारत के लिए आंशिक आय समर्थन योजना की तरह होगा। मांग पर इसका वृद्धिशील प्रभाव उल्लेखनीय होगा, किसानों की आय पर इसका उल्लेखनीय प्रभाव होगा और इस योजना के कारण अतिरिक्त खर्च का बोझ अपेक्षाकृत मध्यम होगा।

अगर हर किसान परिवार को सालाना नकदी अंतरण की राशि दोगुना भी की जाती है तो भी अतिरिक्त खर्च केवल 90,000 करोड़ रुपये होगा। संक्षेप में कहें तो 2020-21 के आम बजट में कांग्रेस की न्याय (न्यूनतम आय योजना) की अपने ढंग से पैकेजिंग की जा सकती है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दम मिलेगा।

कृषि पर सरकार का खर्च केवल पीएम-किसान या फसल बीमा, कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी या किसानों के लिए पेंशन तक ही सीमित नहीं है। सरकार उर्वरक और खाद्य सब्सिडी पर भी अच्छी खासी राशि खर्च करती है जिससे अप्रत्यक्ष तौर पर किसानों को फायदा होता है। उदाहरण के लिए 2019-20 में सरकार के उर्वरक सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये और खाद्य सब्सिडी पर 1.84 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। इस तरह 2019-20 में किसानों की कल्याणकारी योजनाओं पर सरकारी खर्च करीब 4.15 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जबकि 2018-19 में यह राशि 3.28 लाख करोड़ रुपये और 2017-18 में 2.19 लाख करोड़ रुपये थी।

इस सब्सिडी को ज्यादा कारगर और लाभार्थियों के लिए लक्षित बनाने के वास्ते बजट में क्या किया जा सकता है? अनाज की खरीद में भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के इस्तेमाल के लिए बजट में एक योजना पर विचार होना चाहिए और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। पहले ही सरकार यह सुनिश्चित कर चुकी है कि उर्वरक पर सब्सिडी किसानों को वास्तविक बिक्री के आधार पर ही जारी की जाए। अब ऐसी व्यवस्था का समय आ गया है कि गेहूं और धान का खरीद मूल्य सीधे किसानों के बैंक खाते में जाए। अगर जरूरी हुआ तो इसके लिए आधार आधारित पहचान प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओडिशा और पंजाब की सरकारें अपने राज्यों में इसी तरह की योजना लाने की कोशिश कर रही हैं। 2020-21 के आम बजट में पूरे देश में इस तरह की योजना लाने पर विचार किया जा सकता है। इससे सब्सिडी योजनाओं की खामियों को दूर कर इनकी लागत में कटौती हो सकती है। साथ ही देश में मौजूदा अनाज खरीद प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है।

अंत में बजट में कृषि में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर हाल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक बजट में 22,000 ग्रामीण हाट को ग्रामीण कृषि बाजार में अपग्रेड करने के लिए राशि आवंटित की जानी चाहिए। बजट में आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में निवेश की योजना का खाका तो पेश किया ही जा सकता है।

कानाफूसी

मध्य प्रदेश में कौन बनेगा प्रदेशाध्यक्ष?

भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष तलाश कर रही है। इस बीच मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी दूसरे कार्यकाल के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हाल ही में राकेश सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन महासचिव सुहास भगत के बीच बंद कमरे में एक बैठक आयोजित की गई। बाद में तोमर के आवास पर तोमर और सिंह की एक और बैठक आयोजित हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद नहीं थे। इस संबंध में चौहान ने कहा कि वह दिल्ली में राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक में शिरकत कर रहे थे लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि राज्य की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता तेजी से समाप्त हो रही है।

षड्यंत्र की बू

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मुख्य सभागार में बुधवार को जब एमेजॉन डॉटकॉम के प्रमुख जेफ बेजोस ने कंपनी के सम्मेलन में बोलना शुरू किया तो वहां बड़ी तादाद में कंपनी के रिटेलर और एमेजॉन पार्टनर मौजूद थे। परंतु इनमें से ज्यादातर लोग जो तस्वीरें खींचकर ऑनलाइन अपलोड करना चाहते थे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उनके मोबाइल में पर्याप्त सिग्नल नहीं आ रहे थे। चूंकि इस कार्यक्रम में एक प्रतिद्वंद्वी दूरसंचार कंपनी कारोबारी भागीदार थी इसलिए लोगों ने इसमें षड्यंत्र सूंघना शुरू कर दिया।

आपका पक्ष

पृथ्वी की रक्षा परम कर्तव्य समझा जाए

जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम तुरंत इलाज कराने लगते हैं। बीमारी और नहीं बढ़े तथा यह जानलेवा न बने इसके लिए परहेज करने लगते हैं। लेकिन आज हमारी गलतियों के कारण पृथ्वी बीमार हो रही है। बहुत अफसोस की बात है कि इसके इलाज के लिए हम गंभीर नहीं हैं। महात्मा गांधी ने पर्यावरण और सतत विकास पर कहा था कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही उसके विनाश के बीज निहित है। आधुनिकता और भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में इंसान को अपने वातावरण का भी ख्याल नहीं रहा है। वातावरण के प्रति लापरवाही जीव जंतुओं और अब खुद इंसान की जान पर भी भारी पड़ना शुरू हो चुका है। इसका खुलासा विभिन्न संस्थाओं ने भी करना शुरू कर दिया है। पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण के कारण ही देश में जानलेवा बीमारियां बढ़ती जा रही है। आज जिस तरह पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से चिंतित है उसके लिए जरूरी है कि प्राथमिक और युद्धस्तर पर अभियान चलाए जाएं। आज लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जरूरत है। अगर भारत की बात की जाए तो यहां दिन प्रतिदिन हरे भरे जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। सड़कों का विस्तार करने के लिए भी वृक्षों को काटा जा रहा है। जहां कभी हरे भरे खेत थे या बगीचे होते थे वहां अब कई भवन या फिर औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो गई हैं। आज पृथ्वी पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि इतना बढ़ चुका है कि यहां रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अत: पृथ्वी को हर तरह के प्रदूषण से बचाने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए, तभी पृथ्वी स्वर्ग बनी रह सकती है। अन्यथा एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब धरती पर प्राणी जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पर्यावरण बचाने के लिए पटना में बुधवार को महिलाओं ने मशाल जुलूस निकाला *फोटो-पीटीआई*

आर्थिक सुस्ती को दूर करने की बारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस बजट का देश एकटकी लगाए इंतजार कर रहा है कि आर्थिक सुस्ती को कम करने एवं विकास दर में वृद्धि करने के लिए क्या परिवर्तन किया जाएगा। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उस देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बताती है। देश की अर्थव्यवस्था छह साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। वर्ष 2017-18 में विकास दर 8.1 प्रतिशत के साथ उच्चतम स्तर पर थी। वर्तमान में विकास दर 4.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। अर्थव्यवस्था में तेजी के बाद मंदी या सुस्ती देखने को मिली है। एनएसओ की एक रिपोर्ट के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 10.1 प्रतिशत पर आ गई है। आर्थिक सुस्ती उद्योग में डर पैदा कर देता है जिससे वह निवेश करने का जोखिम नहीं लेना चाहता है। उत्पादक अपने उत्पादन के तरीके बदल देते हैं जिससे विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाता है। बहरहाल आर्थिक सुस्ती की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों से निर्यात में ठहराव आया है। इसमें वृद्धि के लिए सरकार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नए सिरे से विचार करना चाहिए।

तारांजलि पटेल, रायपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

आयातित खाद्य तेल स्टॉक में गिरावट

खाद्य तेल का औसत स्टॉक 30 दिन से कम होकर 22 दिन का ही रह गया

राजेश भयानी
मुंबई, 16 जनवरी

आयातित खाद्य तेल का स्टॉक पिछले कई साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। विदेशों से आने वाले खाद्य तेल का औसत स्टॉक 30 दिन की खपत के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन जनवरी की शुरुआत में इसमें गिरावट आई है और यह कम होकर इस स्तर पर आ गया है जो केवल 22 दिन के लिए ही पर्याप्त है।

उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) के अनुसार विभिन्न बंदरगाहों पर 1 जनवरी तक खाद्य तेल कम होकर अनुमानित रूप से 8,60,000 टन (20 प्रतिशत रिफाइंड तेल) रह गया है। आयात किए जाने वाले स्टॉक में पिछले चार महीने से कमी आ रही है। बंदरगाहों पर जमा और आयात किया जा रहा कुल स्टॉक 13.6 लाख टन बताया जाता है जो पिछले महीने के मुकाबले नौ प्रतिशत कम है। पिछले साल के 20.3 लाख टन की तुलना में इसमें एक-तिहाई गिरावट आई है। भारत की मासिक जरूरत करीब 19 लाख टन रहती है। सामान्य रूप में यह 30 दिन का स्टॉक होता है। इसके मुकाबले फिलहाल 22 दिनों की जरूरत के बराबर का स्टॉक है। मई 2019 में बंदरगाहों पर उपलब्ध और आयात किया जाने वाला स्टॉक 23.6 लाख टन था।

एसईए के कार्याकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा कि पाम तेल के दामों में काफी तेजी से इजाफा हुआ है जिसने लागत बढ़ा दी है। सोयाबीन जैसी फसल को हुए भारी नुकसान के कारण घरेलू दाम सामान्य रूप से ज्यादा हैं। दामों में अधिकता से उपभोग पर भी असर पड़ा है। देश में रिफाइंड पाम तेल आयात की अधिकता रोकने के लिए जनवरी के बाद से रिफाइंड (आरबीडी) पाम तेल और पामोलिन का आयात प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। भारत मुख्य रूप से आरबीडी पामोलिन मलेशिया से आयात करता है। अब इस आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (बीजीएफटी) द्वारा जारी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर डीजीएफटी आयात के लिए लाइसेंस जारी करता है तो ऐसे में एसईए ने प्रति माह केवल 50,000 टन की सीमा रखने का सुझाव दिया है। हालांकि चूंकि मलेशिया से आयात रोक दिया गया है, इसलिए खरीदारों ने इंडोनिशया से पाम ऑयल खरीद के लिए करीब 10 डॉलर अधिक देने शुरू कर दिए हैं।

एसईए के अनुसार भारत का पाम तेल आयात दिसंबर 2019 में 8.64 प्रतिशत घटकर 7,41,490 टन रह गया है। भारत ने दिसंबर 2018 में 8,11,700 टन पाम तेल का आयात किया था। देश का कुल वनस्पति तेल आयात दिसंबर 2019 में घटकर 11.28 लाख टन रह गया जो पिछले साल इस अवधि में 12.11 लाख टन था। देश के कुल वनस्पति तेल आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी 60 फीसदी से अधिक रहती है। पाम तेल उत्पादों में से कच्चे पाम तेल (सीपीओ) का आयात दिसंबर 2019 में घटकर 6,31,824 टन रह गया, जो एक साल पहले 6,70,244 टन था। आरबीडी पामोलिन का आयात घटकर 94,816 टन रह गया, जो पहले 1,30,459 टन था। कच्चे पाम कर्नेल तेल (सीपीकेओ) का आयात पहले के 10,997 टन से बढ़कर 14,850 टन हो गया। दिसंबर 2019 के दौरान सूरजमुखी तेल का आयात घटकर 1,97,842 टन रह गया, जो साल भर पहले 2,35,824 टन था। हालांकि इस दौरान सोयाबीन तेल का आयात 85,404 टन से बढ़कर 1,68,048 टन हो गया।

दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक भारत द्वारा खरीद कम किए जाने के कारण मलेशिया के पाम तेल के दामों पर दबाव बन सकता है, हालांकि इससे सोया तेल के दामों को समर्थन मिलेगा। भारत सालाना 90 लाख टन से ज्यादा पाम तेल की खरीद करता है। यह मुख्य रूप इंडोनेशिया और मलेशिया से तेल खरीदता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक है। इसके बाद मलेशिया का स्थान आता है। भारत मुख्य रूप से अर्जेंटीना से सोया तेल तथा यूक्रेन और रूस से सूरजमुखी तेल खरीदता है।

पिछले साल से एक तिहाई तक की कमी

- एसईए के अनुसार विभिन्न बंदरगाहों पर 1 जनवरी तक खाद्य तेल कम होकर 8,60,000 टन (20 प्रतिशत रिफाइंड तेल) रह गया
- आयात वाले स्टॉक में पिछले चार महीने से कमी आ रही है
- बंदरगाहों पर कुल स्टॉक 13.6 लाख टन है जो पिछले महीने के मुकाबले 9 प्रतिशत कम है
- पिछले साल के 20.3 लाख टन की तुलना में इसमें एक-तिहाई गिरावट आई
- भारत की मासिक जरूरत करीब 19 लाख टन रहती है और 30 दिन का स्टॉक रहता है

पाम तेल रोक पर भारत से बात कर रहा मलेशिया

बढ़ते कारोबारी विवाद पर मलेशिया चिंतित

रॉयटर्स
कुआलालम्पुर, 16 जनवरी

भारत द्वारा पाम तेल आयात पर लगाए गए नए प्रतिबंध से संबंधित चिंताओं को हल करने के प्रयास के तहत मलेशिया भारत सरकार और कारोबार के अधिकारियों के साथ बात कर रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते कारोबारी विवाद के बीच मलेशिया की एक मंत्री ने आज यह जानकारी दी।

भारत सरकार ने मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद द्वारा भारत की हालिया नीतियों के खिलाफ बयानबाजी पर आपत्ति जताई थी। आलोचक इन नीतियों को मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव बता रहे हैं और मलेशिया मुस्लिम बहुल देश है। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल खरीदार भारत ने पिछले सप्ताह रिफाइंड पाम तेल आयात पर रोक लगाई थी और कारोबारियों को अनौपचारिक तौर पर मलेशिया से सभी प्रकार के पाम तेल आयात को रोकने के लिए कहा था। मलेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम तेल निर्यातक और उत्पादक देश है।

रॉयटर्स ने बुधवार को सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि भारत, मलेशिया से पेट्रोलियम, एल्युमीनियम की सिल्लियों, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, कंप्यूटर के पुर्जे और माइक्रोप्रोसेसर के आयात पर भी रोक लगा सकता है। अलबत्ता अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मलेशिया की प्रमुख औद्योगिक मंत्री और पाम तेल की प्रभारी तेरेसा कोक ने भारत के पाम तेल आयात के नए नियमों का उल्लेख करते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस साल हमें अपने कुछ प्रमुख बाजारों में और चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं।

कोक ने कहा कि वह इस मसले को लेकर मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त के साथ संपर्क में हैं। इस कार्यक्रम से इतर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हमारे लिए राजनयिक मार्गों और हितधारकों के जरिये उनसे संपर्क करना महत्त्वपूर्ण है। हम संपर्क जारी रखेंगे।

मलेशिया के पाम विक्रेताओं के लिए अच्छी खबर है कि बांग्लादेश के कृषि मंत्री ने रॉयटर्स से कहा है कि अगर मलेशिया वाजिब दाम लगाता है, तो उनका देश मलेशिया से अतिरिक्त खरीद के लिए तैयार है। दक्षिण एशिया का यह देश मुख्य रूप से इंडोनेशिया से खरीद करता है। मलेशिया-भारत के इस विवाद से उसे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने की संभावना है। मुस्लिम जगत के मसलों पर मुखर रहने वाले 94 वर्षीय महातिर ने गुरुवार को एक कार्यक्रम से इतर भारत के साथ इस विवाद से संबंधित रॉयटर्स के एक सवाल को नजरअंदाज कर दिया।

भारत के कारोबारियों का कहना है कि वर्ष 2019 में भारत, मलेशिया का सबसे बड़ा पाम तेल खरीदार था। इस वर्ष भारत ने 44 लाख टन खरीद की थी। अगर संबंधों में सुधार नहीं होता, तो वर्ष 2020 खरीद गिरकर 10 लाख टन से कम रह सकती है।

मलेशिया के अधिकारी कह रहे हैं कि संभावित नुकसान की भरपाई के लिए वे पाकिस्तान, फिलीपींस, म्यांमार, वियतनाम, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया, जॉर्डन, कजाकस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों को बिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं।

मलेशिया के लिए चिंता की एक बात यह है कि बुधवार को अमेरिका और चीन के बीच शुरुआती व्यापारिक समझौते के बाद चीन, अमेरिका से सोया तेल की खरीद बढ़ा सकता है और मलेशिया से पाम तेल की खरीद कम कर सकता है।

- भारत ने पिछले सप्ताह लगाया था रिफाइंड पाम के तेल आयात पर प्रतिबंध
- भारत का सबसे बड़ा रिफाइंड पाम तेल निर्यातक रहा है मलेशिया
- मलेशिया नुकसान की भरपाई के लिए पाकिस्तान, फिलीपींस, म्यांमार, वियतनाम, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया, जॉर्डन, कजाकस्तान और उज्बेकिस्तान को बिक्री करने की कोशिश कर रहा

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 16	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,778.5	4.4	2,044.0	7.4
Copper	6,232.0	9.6	6,597.1	10.6
Nickel	13,950.0	-18.0	14,942.2	-16.3
Lead	1,960.5	-9.8	2,213.1	4.7
Tin	17,430.0	4.8	18,395.8	5.6
Zinc	2,390.0	-2.1	2,607.8	-1.4
Gold ($/ounce)	1,556.3*	4.4	1,742.4	4.8
Silver ($/ounce)	18.0*	3.5	20.3	3.9
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	64.1*	9.5	64.4	8.7
Natural Gas ($/mmBtu)	2.1*	-7.4	2.1	-8.2
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	198.0	14.7	319.1	10.3
Maize	191.8*	5.5	336.1	13.2
Sugar	396.5*	16.0	493.2	0.6
Palm oil	775.0	45.5	1,258.1	46.6
Rubber	1,581.2*	15.3	1,945.3	15.8
Coffee Robusta	1,298.0*	7.2	1,931.2	1.8
Cotton	1,538.8	8.1	1,630.2	1.5

* As on Jan 16, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 70.8& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	95.9	32375
Oil and Oilseeds	404.8	79276
Spices	0.2	9
Metal(Jan 15)		
Metal- non ferrous	6168.5	50318
Metal- precious	9796.7	413
Oil and gas(Jan 15)		
Gas	3045.6	62131
Oil	12981.1	1854

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	136.7	122222
Grains	104.3	97810
Oil and Oilseeds	1081.9	505580
Others	93.8	66805
Pulses	79.2	26370
Spices	50.7	23701

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Feb 14)	3943.7	3.2
Nickel (Jan 31)	1049.5	3.1
Silver (Mar 05)	46389.0	1.1
Silver Mini (Feb 28)	46404.0	1.0
Silver Micro (Feb 28)	46399.0	1.0
Gold Guinea (Jan 31)	31748.0	0.5
Losers (* % Change)		
Natural Gas (Jan 28)	151.3	-4.7
Crude Oil (Jan 17)	4100.0	-0.9
Mentha Oil (Jan 31)	1262.8	-0.9
Cotton (Jan 31)	19660.0	-0.7
Aluminium Mini (Jan 31)	139.7	-0.5
Kapas (Apr 30)	1121.0	-0.4

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Jeera Unjha (Jan 20)	15805.0	1.3
Coriander-Kota (Jan 20)	6459.0	0.4
Barley Jaipur (Apr 20)	1725.0	0.2
Losers (* % Change)		
GuarGum 5T-Jodhpur (Jan 20)	7199.0	-1.7
Guar Seed 10 (Jan 20)	4066.0	-0.7
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jan 20)	913.4	-0.7
Mustard Seed Rape Oil (Jan 20)	4338.0	-0.7
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6376.0	-0.6
CastorSeed New-Disa (Jan 20)	4106.0	-0.5
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1122.5	-0.4
CottonSeed Oil-Akola (Jan 20)	2062.0	-0.3
Chana-Bikaner (Jan 20)	4460.0	-0.2

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	1.8
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19660.0	1.6
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	46399.0	0.3
Silver Ahm (Mar 05)	46389.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1262.8	-9.4
Lead Min Mumbai (Jan 31)	152.7	-2.8
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	181.8	-2.5
Lead Mum (May 29)	153.3	-2.4
Alumini-Mumbai (Jan 31)	139.7	-2.2
Copper Mum (Jan 31)	455.3	-2.2
Zinc Mumbai (May 29)	184.5	-1.1
Gold Petal-Mumbai (Jan 31)	3957.0	-0.8

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	826.1	4.1
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6376.0	3.2
Moong-Merta City (Jan 20)	7806.0	1.4
Maize-Sangli (Jan 20)	2050.0	1.0
Bajra-Jaipur (Jan 20)	1981.0	0.9
29 mm Cotton-Rajkot (Jan 20)	19590.0	0.7
Discount over spot price (In %)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6459.0	-6.2
Soy Bean Indore (Jan 20)	4236.0	-2.6
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Jan 20)	7199.0	-1.8
Bajra-Delhi (Jan 20)	1981.0	-0.9
Jeera Unjha (Jan 20)	15805.0	-0.8

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	109.....(109)
Aluminium ingots /kg	145.....(145)
Brass sheet cutting /kg	327.....(325)
Brass utensil scraps/kg	310.....(312)
Copper heavy scrap /kg	435.....(435)
Copper utensil scraps/kg	408.....(405)
Copper wire bar /kg	468.....(467)
Lead ingots /kg	157.....(157)
Nickel Cathodes /kg	1060.....(1040)
Tin slabs /kg	1305.....(1300)
Zinc slabs /kg	185.....(185)
Source:Bombay Metal Exchange	
Cotton	**Mumbai**
Bengal Deshi /Qtl	10264.....(10264)
DCH - 32 /Qtl	11445.....(11585)
Jaydhar /Qtl	9983.....(9983)
Shankar- 6 /Qtl	11248.....(11389)
Source:Cotton Association of India	
Oil	**Mumbai**
Castor FSG /10kg	878.....(878)
Castor Comm /10kg	868.....(868)
Groundnut oil /10kg	1150.....(1160)
Palm oil /10kg	885.....(892)
Sunflower exp ref /10kg	930.....(930)
Sunflower oil exp /10kg	900.....(900)
Soyabean ref / 10kg	920.....(925)
Source:Bombay Commodity Exchange	

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3412-3585.....(3412-3580)
Source:Bombay Sugar Merchants Association	

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	57.98.....(57.81)
Brent Crude (UK)	64.53.....(64.4)
Brent Crude (WTI)	57.81.....(57.81)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.13.....(2.12)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	315.51.....(321.71)
Naptha spot /Rs/MT	45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.....(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com	

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	39740.....(39654)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	39900.....(39813)
Silver.999/ kg	46270.....(45960)
Source:India Bullion & Jewellers Association	

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	19569.60	19460.45
Alumini-Mumbai (M)	1 K	143.70	142.85
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1970.00	2000.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1979.40	1963.65
Barley Jaipur (N)	1 Q	2198.65	2187.80
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3833.00	3950.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4205.00	4206.25
Castor Seed-Kadi (N)	X	4210.00	4125.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4377.50	4377.50
Chana Delhi (N)	1 Q	4593.65	4550.00
Chana-Akola (N)	X	4384.40	4375.00
Coriander-Gondal (N)	X	6600.00	6644.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6900.00	6825.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6894.35	6883.95
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2111.40	2100.00
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2087.20	2071.35
Cotton-Kadi (N)	1 B	19600.65	19301.90
CPO-Kandla (M)	10 K	826.80	805.80
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	824.05	793.80
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	825.00	825.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	902.25	902.65
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1542.55	1542.90
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3433.75	3432.75
Gold Ahm (M)	10 G	39602.00	39727.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	31809.00	31909.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3979.00	3990.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7416.40	7328.15
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4068.90	4014.70
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4050.00	4025.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1131.95	1130.20
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	100.75	102.70
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16400.00	16200.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16061.75	15939.45
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	905.00	900.20
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1073.65	1050.60
Kapas-Rajkot (N)	X	1072.55	1062.30
Lead Mum (M)	1 K	155.00	157.00
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1969.40	1969.40
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2391.35	2376.00
Maize-Erode (N)	X	2045.00	2045.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2230.00	2260.00
Maize-Sangli (N)	X	2048.45	2030.00
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	5000.00	4937.50
Moong-Merta City (N)	1 Q	7800.00	7700.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4488.50	4437.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	1027.50	1055.80
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3207.00	3214.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3225.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	343.60	343.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	34500.00	34500.00
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	893.75	885.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	815.00	797.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1953.35	1926.65
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5189.75	5180.40
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	892.50	892.50
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	921.15	910.85
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	927.65	920.60
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	942.50	933.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13650.00	13800.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13700.00	13800.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46189.00	46281.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4366.00	4350.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4292.50	4267.25
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4416.25	4393.50
Soy Bean-Akola (N)	X	4293.00	4293.00
Soymeal Indore (N)	1 T	35250.00	34500.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	922.20	917.80
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	32400.00	32320.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	32520.00	32310.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	29630.00	29560.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3300.00	3305.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3428.55	3404.60
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3307.50	3311.65
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3495.25	3490.50
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3341.35	3336.40
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3169.00	3166.10
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6179.75	6179.75
Wheat Delhi (N)	1 Q	2350.00	2350.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2261.65	2266.65
Wheat New Indore (N)	1 Q	2330.00	2300.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2150.00	2132.50
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2335.00	2350.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5700.00	5600.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	6000.00	6000.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	185.65	186.50

* as on Jan 15, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

DAY SESSION

दिवस सत्र (गुरुवार)

कृषि जिंस

Cotton

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19770, 19800, 19610, 19660	4936	659	19490
Feb 28	20070, 20070, 19880, 19940	2670	390	10187
Mar 31	20260, 20270, 20150, 20180	366	55	1645
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Jan 20	2060, 2130, 2050, 2062	1620	119	4760
Feb 20	2072, 2095, 2061, 2074	40310	2741	92780
Mar 20	2102, 2121, 2088, 2101	5160	481	14310
Apr 20	2138, 2145, 2124, 2134	700	68	5510
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1123, 1127, 1117, 1121	532	79	1032
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1124, 1128, 1117, 1122.5	1661	828	4492

Grains

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1725, 1725, 1725, 1725	50	2	1580
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4066, 4066, 4066, 4066	5	1	2165
Feb 20	4130, 4148, 4084, 4100	24095	2767	89115
Mar 20	4170, 4184, 4126, 4148	1240	209	3560

Oil and Oilseeds

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4118, 4122, 4080, 4106	1195	50	2500
Feb 20	4148, 4166, 4100, 4140	4120	403	26570
Mar 20	4170, 4170, 4128, 4152	250	18	7240
Apr 20	4150, 4152, 4150, 4152	260	8	2995
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	818.9, 824.9, 794, 802.7	21400	1644	35910
Feb 28	813.4, 817.6, 787, 797.2	23090	1651	34620
Mar 31	802.5, 802.5, 779.1, 788.6	3940	234	8230
Apr 30	785.2, 785.2, 778.8, 782	40	3	210
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jan 31	1271.6, 1273.8, 1259.1, 1262.8	119.52	279	263.16
Feb 28	1282, 1282.5, 1270, 1272.5	11.88	32	41.4
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4390, 4390, 4310, 4338	400	22	2350
Feb 20	4341, 4370, 4280, 4307	16940	1325	13030
Apr 20	4382, 4403, 4291, 4320	12680	975	10330
May 20	4400, 4413, 4310, 4371	740	72	1330
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	925.6, 929, 912.2, 913.4	4455	334	5310
Feb 20	906, 908.6, 888.6, 895.2	41505	4258	58670
Mar 20	895.6, 895.8, 873, 883.2	16690	1651	28080
Apr 20	884, 888, 865, 875.4	1075	189	3125
May 20	878.2, 878.2, 862.2, 865	60	12	55
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4242, 4248, 4192, 4236	2530	225	8840
Feb 20	4190, 4240, 4158, 4212	62065	6420	192860
Mar 20	4210, 4248, 4160, 4224	15325	2141	106885
Apr 20	4236, 4268, 4188, 4242	4110	575	32745
May 20	4260, 4294, 4214, 4244	375	67	2660
Jun 19	4272, 4272, 4272, 4272	5	1	5

Others

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7247, 7275, 7180, 7199	280	40	435
Feb 20	7325, 7389, 7250, 7274	9905	1517	57535
Mar 20	7443, 7485, 7350, 7371	2615	373	8835

Pulses

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4466, 4470, 4460, 4460	1330	46	1640
Mar 20	4343, 4343, 4283, 4287	15390	1005	21740
Apr 20	4326, 4326, 4276, 4281	1610	151	2780
May 20	4325, 4325, 4325, 4325	10	1	130

Spices

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	3933.7, 3972.8, 3933.7, 3943.7	0.4	4	7.3
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Jan 20	6469, 6500, 6243, 6459	1250	123	940
Apr 20	7025, 7030, 6800, 6984	2520	219	9640
May 20	6951, 6960, 6900, 6960	40	4	210
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	15850, 15850, 15750, 15805	45	9	72
Mar 20	15125, 15235, 15050, 15105	867	270	1812
Apr 20	14960, 14995, 14875, 14935	276	91	747
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6448, 6468, 6310, 6376	785	142	5630
Apr 20	6350, 6364, 6220, 6282	305	60	4565
May 20	6356, 6356, 6306, 6306	10	2	85

धातु

Metal- non ferrous

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	139.75, 140.65, 139.75, 140.5	3476	2377	4552
Feb 28	140.75, 141.4, 140.5, 141.3	347	268	1550
Copper MCX(1 K)				
Jan 31	454.25, 455.95, 453.5, 455.65	11737.5	3930	12862.5
Feb 28	455.1, 457.15, 454.6, 456.65	875	272	4112.5
Lead MCX(1 K)				
May 29	153.7, 153.7, 153.7, 153.7	1	1	4
Lead Mini MCX(1 K)				
Jan 31	153, 153.2, 152.45, 152.95	5033	3010	6

एमेजॉन नहीं कर रही एहसान: गोयल

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की दिलचस्पी यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने में है

नेहा अलावधी और शुभायन चक्रवर्ती

ई-कॉमर्स क्षेत्र के दिग्गज कंपनी एमेजॉन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेफ बेजोस द्वारा देश में निवेश की घोषणा के एक दिन बाद ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एमेजॉन एक अरब डॉलर का निवेश कर भारत पर कोई अहसान नहीं कर रही है। उन्होंने रायसीना डायलॉग 2020 के एक सत्र में कहा, 'कंपनी भले ही एक अरब डॉलर का निवेश कर सकती है लेकिन अगर उसे अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है तो वह उस अरब डॉलर का इंतजाम भी कर रही होगी ऐसे में कंपनी एक अरब डॉलर का निवेश कर भारत पर कोई एहसान नहीं कर रही है।'

बेजोस सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों पर केंद्रित एमेजॉन संभव के पहले संस्करण में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर शख्स माना जाता है जिनकी हैसियत 117 अरब डॉलर है। नई दिल्ली में उन्होंने घोषणा की कि कंपनी एक अरब डॉलर का निवेश करेगी जो देश में पिछले पांच सालों में किए गए 5 अरब डॉलर निवेश के अतिरिक्त होगा।

ताजा निवेश देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले कारोबार (एमएसएमई) के डिजिटलीकरण के लिए होगा और इससे एमएसएमई निर्यात वर्ष 2025 तक 10 अरब डॉलर करने में मदद मिलेगी। सिएटल मुख्यालय वाली कंपनी का मकसद निवेश के जरिये 1 करोड़ एमएसएमई का डिजिटलीकरण करना और साथ ही एमेजॉन के मंच पर दुनिया भर में अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री कर कारोबार में वृद्धि करना है। साफतौर पर गोयल कंपनी की निवेश की घोषणा से संतुष्ट नहीं थे। एमेजॉन के घाटे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी अपने घाटे की भरपाई करने के लिए निवेश कर रही है। उन्होंने कहा एक निष्पक्ष बाजार मॉडल में कारोबार 10 अरब डॉलर का है और अगर कंपनी को अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से यह सवाल पैदा होता है कि यह घाटा कैसे हो रहा है।

उन्होंने कहा, 'ऑनलाइन कंपनियों को यह बताने की जरूरत है कि अगर वे कोई अनुचित कदम नहीं उठाती हैं या फिर अगर बाजार खराब करने वाली कीमत पर सामान उपलब्ध नहीं करा रही हैं तब उन्हें इतना घाटा कैसे हो सकता है।'

> ऑनलाइन कंपनियों को यह बताने की जरूरत है कि अगर वे कोई अनुचित कदम नहीं उठाती हैं या फिर अगर बाजार खराब करने वाली कीमत यानी सस्ती दरों पर ग्राहकों को सामान उपलब्ध नहीं करा रही हैं तब उन्हें इतना बड़ा घाटा कैसे हो सकता है

पीयूष गोयल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

गोयल ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने एमेजॉन और फ्लिपकार्ट से जुड़े कई मामलों में जांच का आदेश दिया है जो देश की दो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। उन्होंने कहा कि कंपनियां जब तक नियमों का पालन करेंगी तब तक वे देश में अपना कारोबार करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि देश में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए 49 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा तय की गई है। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को भारतीय नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा और कानून में सेंध लगा कर पिछले दरवाजे से देश के बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर उनसे सवाल किए जाएंगे और जांच प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

अंकुश नहीं

सरकार मलेशिया और तुर्की से आयात पर अंकुश लगाने पर विचार नहीं कर रही है। गोयल ने कहा कि भारत सभी देशों को उचित अवसर देने और उनके साथ समान व्यवहार पर यकीन करता है। उन्होंने कहा, 'यदि कुछ अंकुशों से मलेशिया प्रभावित हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इससे प्रभावित होने वाला वह एकमात्र देश है। भारत को निर्यात करने वाले अन्य निर्यातक भी इससे प्रभावित होंगे। सरकार ने 8 जनवरी को रिफाइंड पाम तेल के आयात पर अंकुश लगाया है। इससे मलेशिया पर असर पड़ने की संभावना है। इंडोनेशिया और मलेशिया पाम तेल का निर्यात करने वाले दो प्रमुख देश हैं। मलेशिया द्वारा नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर मुद्दे पर बयान के बाद यह कदम उठाया गया है। तुर्की ने भी कश्मीर की स्थिति को लेकर भारत की आलोचना की है।

बातचीत जारी

गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ व्यापार मसलों के समाधान को लेकर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापार रिश्तों को बढ़ा सकते हैं जो भविष्य में तरजीही या मुक्त व्यापार समझौता का रूप ले सकता है। गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की दिलचस्पी यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने में है।

फिजिटल होगा अहम: बियाणी

फ्यूचर समूह के संस्थापक किशोर बियाणी ने गुरुवार को कहा कि दुकानों और डिजिटल खुदरा स्टोर के अपने फायदे और चुनौतियां होती हैं लेकिन इन दोनों के मेल वाले मॉडल 'फिजिटल' से कारोबार को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है। बियाणी ने एमेजॉन के संभव कार्यक्रम में कहा कि दुकानों और डिजिटल खुदरा की शुरुआत अलग-अलग दौर में हुई है लेकिन अगले 3-4 सालों में ये दोनों एक मंच पर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि एमेजॉन इंडिया और फ्यूचर समूह ने लंबी अवधि के लिए एक कारोबारी समझौता किया है जिसके तहत फ्यूचर के खुदरा स्टोरों और एमेजॉन के ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिये ब्रांड की पहुंच के दायरे को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

फ्यूचर समूह के 1,700 स्टोर बिग बाजार, इजीडे, हेरिटेज फ्रेश, नीलगिरी और डब्ल्यूएच स्मिथ जैसी इकाइयों के तहत संचालित होते हैं और इसके खुदरा नेटवर्क में 35 करोड़ ग्राहकों की आवक होती है। बियाणी का कहना है कि दुकानों के खुदरा विक्रेता को डिजिटल माध्यम की जरूरत है और डिजिटल को भी दुकानों की जरूरत है क्योंकि ग्राहकों को जोड़ने और ऑर्डर की पूर्ति करने की भी लागत होती है, ऐसे में हाइब्रिड मॉडल से उनके कारोबार के बेहतर प्रदर्शन करने की गुंजाइश होगी।

देश में एमेजॉन और वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट की देश के ऑनलाइन बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ई-कॉमर्स क्षेत्र का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला बाजार है और इस क्षेत्र का राजस्व 2017 के 29 अबर डॉलर से बढ़कर 2020 में 120 अरब डॉलर हो जाएगा। इस तरह इस क्षेत्र में सालाना 51 फीसदी की दर से वृद्धि हो रही है। एमेजॉन और फ्लिपकार्ट देश के बाजार में कारोबार बढ़ाने के लिए लाखों डॉलर का निवेश कर रही हैं लेकिन कई छोटे कारोबारियों का आरोप है कि इन कंपनियों ने भारी छूट देकर और अनुचित प्रक्रिया के जरिये बाजार हिस्सेदारी पाने की रणनीति अपनाई है।

एजेंसियां

कारोबारियों के लिए निजी ई-स्टोर जल्द

व्यापारियों के प्रमुख संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है कि उसने परीक्षण आधार पर मध्य प्रदेश में व्यापारियों के लिए व्यक्तिगत ई-स्टोर बनाने का पूरा कर लिया है। जल्द इसे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाएगा। कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने गुरुवार को कहा कि वे ई-कॉमर्स के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कैट उन कंपनियों का विरोध कर रही है जो सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का अपने लाभ के लिए उल्लंघन कर रही हैं।

उन्होंने कहा, 'हम ई-कॉमर्स के खिलाफ नहीं हैं। हमारा मानना है कि ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ता भविष्य का कारोबारी मॉडल है। हम व्यापारिक समुदाय के ई-कॉमर्स के साथ तालमेल को देश के प्रत्येक व्यापारी के लिए व्यक्तिगत ई-स्टोर बना रहे हैं।' उन्होंने कहा कि इस परियोजना की परीक्षण प्रक्रिया मध्य प्रदेश में पूरा हो गई है। इसे जल्द राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री को 2024 तक मिल जाएगा नया घर

अर्णव दत्ता

अगर आप प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास के आसपास यातायात पर अक्सर लगने वाली पाबंदियों से परेशान हैं तो जल्दी ही आपको इस समस्या से निजात मिल सकती है। प्रधानमंत्री जब अपने आवास से साउथ ब्लॉक स्थित दफ्तर में जाते हैं, तो जिन सड़कों से उनका काफिला गुजरता है वहां यातायात रोक दिया जाता है। 7, लोक कल्याण मार्ग कई दशकों से प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास रहा है और नौ प्रधानमंत्री इसमें रहे हैं। लेकिन 2024 तक प्रधानमंत्री को नया आवास मिल सकता है।

> संसद की इमारत के पुनर्निर्माण के बजाय संसद परिसर में ही एक नई इमारत बनाई जाएगी

1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो वह 7, लोक कल्याण मार्ग में रहने आए थे। 12 एकड़ में फैला यह परिसर नई दिल्ली के मुख्य वास्तुकार एडविन लुटियंस के डिजाइन पर आधारित है। हालांकि नई पुनर्विकास योजना के मुताबिक रायसिना हिल पर साउथ ब्लॉक के दक्षिण-पश्चिम कोने पर प्रधानमंत्री आवास बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के मौजूदा आवास और साउथ ब्लॉक दफ्तर की दूरी 2.8 किमी है। प्रधानमंत्री का नया आवास बनने से उनके कार्यालय पहुंचने के समय में कटौती होगी। सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की महत्त्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। इसमें संसद की नई इमारत, सभी केंद्रीय मंत्रालयों को करीब लाना और सेंट्रल विस्टा के आसपास स्थित धरोहर इमारतों का पुनर्विकास शामिल है। इसमें लुटियंस की दिल्ली के डिजाइन में बदलाव के कई प्रस्ताव हैं। इस योजना का खाका बनाने का अनुबंध एचसीपी डिजाइन ऐंड प्लानिंग को मिला है। कंपनी के प्रमुख विमल पटेल के मुताबिक यह परियोजना लुटियंस की मूल योजना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि दफ्तर के बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिये सरकार के कामों को मजबूत करना, व्यावहारिक बनाना और उनमें तालमेल बिठाना इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य है। सेंट्रल विस्टा में सभी मंत्रालयों के साथ प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति के आवास भी होंगे। उपराष्ट्रपति का आवास नॉर्थ ब्लॉक के पीछे होगा।

संसद की इमारत के पुनर्निर्माण के बजाय संसद परिसर में ही एक नई इमारत बनाई जाएगी। अभी जिस इमारत में संसद स्थित है उसे 1947 से ही संसद भवन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 13 एकड़ के एक भूखंड पर त्रिकोणीय ढांचा स्थापित किया जाएगा जिसे अभी कार पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें मौजूदा लोक सभा कक्ष से तीन गुना ज्यादा आकार का कक्ष, राज्य सभा कक्ष और एक लाउंज होगा।

7, लोक कल्याण मार्ग दशकों से प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है और इसमें 9 प्रधानमंत्री रहे हैं

हालांकि मौजूदा संसद भवन के उलट लोक सभा के नए कक्ष को संयुक्त सत्र के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें नियमित रूप से 900 लोग बैठ सकेंगे लेकिन इसमें संयुक्त सत्र के दौरान 1,350 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसे मिस्र की संसद की तर्ज पर डिजाइन किया जा रहा है और इसमें हर सांसद को 50 फीसदी ज्यादा जगह उपलब्ध होगी। मौजूदा लोक सभा कक्ष में केवल 552 सांसद बैठ सकते हैं। पटेल ने कहा, 'मौजूदा संसद भवन में वातानुकूलन की व्यवस्था, इंटरनेट और पार्किंग नहीं है। नई इमारत में ये सभी सुविधाएं होंगी।' संसद की नई इमारत में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए इसकी खिड़कियां अलग-अलग तरह की होंगी।

अभी केंद्र सरकार के 51 में से 22 मंत्रालय सेंट्रल विस्टा और इसके आसपास हैं। योजना के मुताबिक राजपथ के दोनों तरफ 10 नई इमारतें बनाई जाएंगी जिनमें सभी मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। एकीकृत भूमिगत पार्किंग के अलावा इन इमारत परिसरों में सीधे दिल्ली मेट्रो की येलो और वॉयलेट लाइनों तक पहुंचने के लिए भूमिगत रास्ते भी होंगे। इंडिया गेट और रायसिना हिल के बीच तीन किमी लंबे सेंट्रल विस्टा में यातायात को कम करने के लिए पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर अंडरपास होंगे।

पटेल ने कहा कि 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए उनकी योजना में लुटियंस के 'रिज टु रिवर' मॉडल को अपनाया गया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना रायसिना हिल के रिज से शुरू होगी और यमुना नदी पर खत्म होगी। वहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के पीछे 48 एकड़ में स्थित जैव विविधता पार्क के अलावा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को भी जनता के लिए खोला जाएगा। इन दो इमारतों को संग्रहालय में बदला जाएगा जिसमें भारत के इतिहास को दिखाया जाएगा। इस तरह देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 एकड़ जमीन जनता के लिए खोली जाएगी।

पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने में नाकाम

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने की बार-बार कोशिश करने पर पाकिस्तान की निंदा की है, जहां उसे चीन की मदद के बावजूद फिर से मुंह की खानी पड़ी। सुरक्षा परिषद में बुधवार को पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा उठाने पर किसी का समर्थन नहीं मिला और उसके पाले में खड़ा उसका सदाबहार सहयोगी चीन अलग-थलग पड़ गया। सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्य देशों ने कहा कि कश्मीर, भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है। इससे पूर्व, चीन ने सुरक्षा परिषद के विमर्श कक्ष में बंद कमरे में हुए विचार-विमर्श के दौरान अन्य मुद्दों के तहत कश्मीर मुद्दे को उठाने की ताजा पैरवी की।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि कई मित्रों ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों के बीच मौजूद समस्याओं को उठाने और उससे निपटने के लिए कई द्विपक्षीय तंत्र हैं। सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल हुए एक यूरोपीय सूत्र ने बताया कि बंद कमरे की बैठक में कश्मीर मुद्दे को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। यूरोप के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि मामले को द्विपक्षीय तौर पर निपटाया जाना चाहिए और यह उनका (भारत-पाकिस्तान) आपसी मामला है।

स्थायी सदस्यता पर मतभेद

चीन ने भारत और ब्राजील की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे को कमतर करने का प्रयास करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर बड़े मतभेद हैं और इसके साथ ही पैकेज समाधान का समर्थन किया। उल्लेखनीय है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने बुधवार को दिल्ली दौरे के दौरान सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था।

लावरोव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि विश्व निकाय में सुधार के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में मतभेद हैं। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक है और उसके पास वीटो शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली निकाय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की कोशिश को चीन वर्षों से आम सहमति नहीं होने का हवाला देकर टाल रहा है जबकि अन्य चार स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने दिल्ली की सदस्यता का समर्थन किया है। चीन के नजदीकी और मित्र देश पाकिस्तान ने भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध किया है।

संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए मिलकर काम करने और दबाव बनाने के लिए भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान ने जी-4 समूह बनाया है। चीन ने हालांकि, वर्ष 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए भारत का समर्थन किया है।

एजेंसियां

आर कॉम की संपत्ति खरीदने वाला कौन ?

सुरजीत दास गुप्ता और देव चटर्जी

भले ही उनकी सालाना रिपोर्ट पर आधिकारिक टैग लाइन 'फंसे कर्ज की वसूली' हो। लेकिन सुर्खियों से परे दिल्ली की यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (यूवीएआरसीएल) अचानक किसी अन्य वजह से सुर्खियों में आई है। यह आईबीसी में उन ऋणग्रस्त दूरसंचार कंपनियों के लिए बोली लगाने वाली प्रमुख कंपनी बनकर उभरी है, जिन्होंने जियो के आने के बाद बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण परिचालन बंद कर दिया।

माना जा रहा है कि यूवीएआरसीएल ने आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम को खरीदने के लिए सर्वाधिक 16,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। ये दोनों कंपनियां आईबीसी में हैं और अनिल अंबानी समूह की इन कंपनियों के पास स्पेक्ट्रम, डेटा सेंटर और रियल एस्टेट परिसंपत्तियां हैं। यूवीएआरसीएल बोली की 30 फीसदी राशि 90 दिनों की अवधि में देने को तैयार है। इसने पिछले साल भी एयरसेल की परिसंपत्तियां खरीदने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी। यह 150 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने को तैयार थी। हालांकि एयरसेल सौदे को बैंकों ने अभी मंजूरी नहीं दी है।

यूवीएआरसीएल की स्थापना 2007 में हुई थी। कंपनी की वेबसाइट पर कहा गया है कि इसकी स्थापना पेशेवरों ने की है, जिसमें 'छह पीएसयू बैंकों और दो बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी है।' इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड और नैशनल इंश्योरेंस शामिल हैं। लेकिन कंपनी की वित्त वर्ष 2019 की सालाना रिपोर्ट में हिस्सेदारी को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदार शिल्पी शर्मा हैं, जो 35.47 फीसदी हिस्सेदारी के साथ प्रवर्तक भी हैं। वहीं बैंकों की संयुक्त रूप से हिस्सेदारी महज 7.7 फीसदी और बीमा कंपनियों की करीब 0.52 फीसदी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर कोई भी बैंक या बीमा कंपनी शीर्ष 10 निवेशकों में शामिल नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 5.4 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी के बारे में भेजे गए सवालों का शर्मा ने कोई जबाव नहीं दिया।

...कैसी रणनीति

- कंपनी ने आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम और एयरसेल समेत ऋणग्रस्त दूरसंचार कंपनियों के लिए बोली लगाई
- चार्टर्ड फाइनैंशियल एनालिस्ट शिल्पी शर्मा 35.47 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदार एवं प्रवर्तक
- कंपनी में छह पीएसयू बैंकों और दो बीमा कंपनियों की 8.22 फीसदी हिस्सेदारी
- अन्य प्रमुख निवेशकों में अनुभव सिक्योरिटीज प्रा. लि., अनुभव बिल्डटेक और सन्मति ट्रेडिंग ऐंड इन्वेस्टमेंट शामिल
- बुक बिल्डिंग के लिहाज से देश की शीर्ष 10 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों में शुमार होने का दावा
- वित्त वर्ष 2019 में आमदनी 121 फीसदी और कर पूर्व लाभ 134 फीसदी बढ़ा

ऐसे में सवाल पैदा होता है कि शिल्पी शर्मा कौन हैं? वह एक चार्टर्ड फाइनैंशियल विश्लेषक हैं। जानकारों का कहना है कि उन्होंने पीएसयू बैंकों की मदद से यूवीएआरसीएल की स्थापना की है। इससे पहले वह कंपनियों को सिंडिकेटेड ऋण लेने में मदद करती थीं। वह बोर्ड की कार्यकारी वाइस चेयरमैन हैं। वेबसाइट पर कहा गया है कि वह पूर्णकालिक निदेशक हैं। पहले वह खुद की सलाहकार कंपनी चलाती थीं और बहुत से उद्योगों के ग्राहकों को बैंकिंग, वित्त और पूंजी बाजार से संबंधित विविध नियामकीय और अनुपालना मामलों में सलाह देती थीं। इसके बाद वह एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की प्रायोजक बनीं। निस्संदेह यूवीएआरसीएल बुक बिल्डिंग के लिहाज से देश की शीर्ष 10 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है, जिसका सीएजीआर पिछले तीन वर्षों के दौरान 109 फीसदी रहा है। वर्ष 2018-19 में कंपनी की आमदनी 36 करोड़ रुपये थी, जो इससे पिछले वर्ष से 121 फीसदी अधिक थी। कंपनी का कर पूर्व लाभ 134 फीसदी बढ़कर 13 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का नेट वर्थ मार्च 2019 में 120 करोड़ रुपये था और इसने प्रत्येक शेयर पर 0.50 रुपये का लाभांश दिया था। हालांकि आरओसी फाइलिंग के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 की शुरुआत में कंपनी पर कर्ज 88 करोड़ रुपये था, जो वर्ष के अंत में 150 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ऐसे में क्या अनिल अंबानी की कंपनियों के लिए यूवीएआरसीएल की बोली को वे बैंक स्वीकार करेंगे, जो ऋणदाताओं की समिति का हिस्सा हैं? एक बैंक अधिकारी ने कहा, 'आरकॉम के लिए किस्तों में भुगतान की पेशकश की गई है, जिसे प्रतिनिधि बैंक बोर्ड स्वीकार नहीं करेंगे।' उन्होंने कहा कि यह एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अग्रिम कम पैसा देना चाहती थी, जिसकी वजह से ही एयरसेल के ऋण का समाधान नहीं हो पाया है। बैंकों को 47,000 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले अग्रिम नकदी बहुत कम मिल रही है। इस वजह से आरकॉम सौदे को संबंधित बैंकों के बोर्डों में मंजूरी मिलना मुश्किल होगा।

दूरसंचार क्षेत्र के विश्लेषकों ने कहा कि यह साफ नहीं है कि अगर सौदे को मंजूरी मिल जाती है तो यूवीएआरसीएल किसी दूरसंचार कंपनी से गठजोड़ करेगी, जो दोनों कंपनियों का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करेगी क्योंकि लाइसेंस की अवधि खत्म होने तक स्पेक्ट्रम को साझा और हस्तांतरित करने की मंजूरी है। आरकॉम का पहले ही रिलायंस जियो के साथ स्पेक्ट्रम साझा करने का समझौता है। इसके तहत जियो आरकॉम के कीमती 800 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल रही है, जो 4जी सेवाओं के लिए अहम है। क्या यूवीएआरसीएल किसी दूरसंचार कंपनी के साथ गठजोड़ करेगी, इस बारे में पूछे गए सवाल का भी जवाब नहीं मिला। इसी आईबीसी प्रक्रिया में जियो ने रिलायंस इन्फ्राटेल को खरीदने के लिए 4,700 करोड़ रुपये की पेशकश की है, जिसके पास टावर और फाइबर परिसंपत्तियां हैं। हालांकि विश्लेषकों ने कहा कि अगर यह आरकॉम के लिए बोली लगाती है तो नियमों के मुताबिक उसे गैर सूचीबद्ध जियो का सूचीबद्ध कंपनी आरकॉम में विलय करना होगा। जियो बड़ा सार्वजनिक निर्गम लाने की योजना बना रही है, लेकिन वह संभव नहीं है।